● वर्ष-4
● अंक-160
रायपुर, गुरुवार 13 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» फिजियोथैरेपी आज की मांग

प्रधानमंत्री मोदी का एलान

अक्तूबर 2025 तक 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य

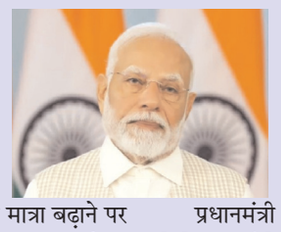

नई दिल्ली। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसी के तहत, सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस दिशा में अगला बड़ा कदम ई 20 फ्यूल होगा, यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसे अक्तूबर 2025 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को तय समय पर पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

भारत में इस समय पेट्रोल में 19 फीसदी एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी, और CO२ उत्सर्जन में कमी हो रही है। पहले, सरकार ने 2030 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे 2025-26 के लिए तय कर दिया गया।

1 अप्रैल 2025 से नए वाहनों में बदलाव अनिवार्य

भारत सरकार ने सभी वाहन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से वे ई20 फ्यूल के अनुकूल इंजन वाले वाहन बनाएं। यह नियम पेट्रोल और हाइब्रिड इंजनों दोनों पर लागू होगा। मारुति सुजुकी, ह्युंदै, होंडा, किआ, स्कोडा, फोक्सवैगन जैसी कंपनियां पहले ही अपने वाहनों को ई20 ईंधन के अनुकूल बना चुकी हैं।

भारत की बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत में 500 मिलियन मीट्रिक टन टिकाऊ फीडस्टॉक (कच्चा जैव ईंधन) उपलब्ध है, जिससे बायोफ्यूल सेक्टर तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस) की स्थापना की गई थी। और इसका लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें अब 28 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस समय भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। और अपनी क्षमता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

ई20 फ्यूल का मतलब है 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण। एथेनॉल एक बायोफ्यूल (जैविक ईंधन) है। जिसे गन्ने या मक्का के शुगर को खमीर से फर्मन्टेशन करके बनाया जाता है। इसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया (एथिलीन हाइड्रेशन) जैसी पेट्रोकेमिकल विधियों के जरिए भी बनाया जा सकता है। एथेनॉल में कुछ संक्षारक (कॉरोसिव) गुण होते हैं, जिससे इसे इस्तेमाल करने के लिए विशेष प्रकार के इंजन और मजबूत कम्पोनेंट्स की जरूरत होती है।

जनजातीय बजट 46% बढ़ाः जोशी

छत्तीसगढ़ के 75 लाख आदिवासियों, 27 लाख किसानों,12 लाख सामान्य व्यापारी,10 एमएसएमई व्यापारी,10 लाख युवाओं व लाखों एससी, एसटी की महिलाओं को बजट से सीधा लाभ

रायपुर। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज केंद्रीय बजट पर विस्तृत जानकारी देने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे और पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केन्द्रीय बजट विकसित भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह वर्ष 2047 विकसित भारत का रोड़ मैप है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एक साथ नगरीय प्रशासन एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आगे बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। युवा, अन्नदाता, गरीब,महिला को ध्यान रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय किए गए हैं। मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा का सशक्तिकरण शुरू हो गया है। राष्ट्र के निर्माण में मध्यम वर्ग देश को शक्ति प्रदान करता है।नयी व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर (अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपए की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को 75, हज़ार की मानक कटौती का लाभ उपलब्ध है। नयी कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को कर में 80 हजार का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री धन - धान्य ,कृषि योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इससे 1.7 करोड किसानों को मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है ब्याज योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। इससे छत्तीसगढ़ के 27 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ होगा।

श्री जोशी ने कहा सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक, आत्म भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल भारत में रोजगार आधारित विकास को गति देंगे।एम एस एम ई को उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद के लिए, सभी एम एस एम ई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्न ओवर सीमा को क्रमश 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और एम एस एम ई को सहायता तक आसान पहुंच की सुविधा मिलेगी। रोगियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। नया आयकर विधेयक स्पष्ट होगा।

सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सुक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज़ क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। 10 हजार करोड़ रुपए के योगदान के साथ एक नया फंड आफ फंड स्थापित किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नयी योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले पांच सालों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए उत्पाद योजना लागू की जाएगी। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारे पेटेंट 2014 के पहले लगभग 400 थे अब एक लाख से ज्यादा है मोदी सरकार रिसर्च को बढ़ावा दे रही है।

क्या हम परजीवियों का वर्ग नहीं बना रहे हैं?

चुनाव पूर्व मुफ्त देने का वादा करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

नईदिल्ली। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त देने का वादा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लोगों को राष्ट्रीय विकास के लिए मुख्यधारा में लाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया जाए। राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के कारण, जो चुनाव के करीब घोषित की गई हैं, जैसे %लड़की बहिन और अन्य योजनाएं, लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। शीर्ष अदालत शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी और कहा कि लोगों को बिना काम किए मुफ्त राशन और पैसा मिले। पीठ ने पूछा कि हम उनके लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए? याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहता, अगर उनके पास काम है। न्यायाधीश ने कहा कि आपको केवल एक तरफा ज्ञान होना चाहिए। मैं एक कृषक परिवार से आता हूं।

13 को संसद में पेश की जाएगी वक्फ कानून रिपोर्ट

नईदिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करने वाली संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की जाएगी। इसे 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले हफ्ते बहुमत से अपनाई गई जेपीसी ने कहा कि उसकी रिपोर्ट में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल हैं, जिससे विपक्ष ने इस अभ्यास को वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास करार दिया। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने 15-11 बहुमत से मसौदा कानून पर रिपोर्ट को अपनाया।

विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया

वक्फ कानून से सबको मिलेगा लाभ

विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया है।

प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ने भारतीय मुसलमानों के बीच आक्रोश और भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी है, प्रमुख आवाजों ने कानून लागू होने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इनोसेंट नेटवर्क द्वारा मराठी पत्रकार संघ में आयोजित एक व्याख्यान श्रृंखला में वक्ताओं ने इस विधेयक को कानूनी सुधारों की आड़ में वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया। कार्यक्रम के दौरान, वकील नौशाद अहमद ने शाहिद आज़मी की हत्या के मुकदमे पर एक अपडेट प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसमें 38 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है।

प्रमुख समाचार

गौरव गोगोई की पत्नी के तार आईएसआई से जुड़े, लगाया आरोप

नईदिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2013 में उनकी शादी के बाद 12 साल तक पत्नी की ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने एलिजाबेथ कोलबर्न के खिलाफ आईएसआई संबंधों के आरोपों का भी

उल्लेख किया और कहा कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आईएसआई से संबंध, युवाओं को ब्रेनवॉशिंग और कट्टरपंथ के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने और पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के संबंध में गंभीर सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। सीएम ने आगे लिखा कि इसके अतिरिक्त, रूपांतरण कार्टेल में भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना गंभीर चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदु पर, जवाबदेही आवश्यक होगी। केवल ज़िम्मेदारी से ध्यान भटकाना या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास आसान पलायन मार्ग के रूप में काम नहीं करेगा। देश पारदर्शिता और सच्चाई का हकदार है।

महाकुंभ भगदड़ - ममता का यूपी सरकार पर हमला

कोलकाता। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मृतकों की सही संख्या जारी नहीं की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य का बजट पेश किए

जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य का बकाया जारी न करने पर निराशा जताई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ की घटना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन वे सही संख्या में मौतों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शोर मचाया कि बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आए, लेकिन आयोजन स्थल पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। महाकुंभ में 29 जनवरी को मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हो गए थे। राज्य सरकार अपना धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बंगाल को लेकर की गई टिप्पणियों का भी जवाब दिया।

50 करोड़ लोग लगा चुके हैं प्रयागराज में डुबकी:योगी

नईदिल्ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 25 करोड़ है और कल तक 50 करोड़ लोग

प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को चोरी-छिपे ऐसा करने की आदत होती है, उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तो लगवा ली लेकिन दुनिया से कहते रहे कि वैक्सीन न लगवाएं। बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने चोरी-छिपे संगम में डुबकी लगाई और वापस आ गए लेकिन जनता से कह रहे हैं कि डुबकी न लगाएं। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं किया। महाकुंभ के पांचवे स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर बुधवार को दोपहर दो बजे तक 1.83 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने इस दौरान, स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई। बुधवार तड़के से ही महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों समेत श्रद्धालुओं का गंगा और संगम घाट की ओर आगमन जारी है।

दिग्विजय सिंह ने संगम में लगाई डुबकी

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 क्षेत्र में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले तीन महाकुंभों में पवित्र स्नान के लिए आता रहा हूं। मेरे लिए यह राजनीति का नहीं बल्कि भक्ति का विषय है। अगर हर सड़क पर पार्किंग की जगह बना दी जाए तो

ट्रैफिक जाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम यहां वीआईपी के तौर पर नहीं बल्कि आम आदमी के तौर पर आए हैं। मैं सभी की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। बाद में दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने और अर्घ्य देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने इस अवसर पर माँ गंगा से देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उनके बेटे विधायक जयवर्धन सिंह ने लिखा कि आज प्रयागराज में मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी के साथ महाकुंभ माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा यमुना सरस्वती, सूर्यदेव भगवान, हमारे पितरों व देवी देवताओं का आशीर्वाद और असीम कृपा सदैव बनी रहे।

जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31 प्रतिशत पर आई

नई दिल्ली। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में धीमी होकर 4.31 प्रतिशत पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.22 प्रतिशत और जनवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत

थी। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इसकी पुष्टि की गई। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 6.02 प्रतिशत रही, जो दिसंबर में 8.39 प्रतिशत तथा एक वर्ष पूर्व माह में 8.3 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। इससे पहले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में उपभोक्ता मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में पांच महीने के निचले स्तर 4.60त्न पर आने की उम्मीद जतायी थी। दिसंबर 2024 खुदरा महंगाई दर 5.22त्न दर्ज की गई थी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2024 में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर धीमी होकर 3.2 प्रतिशत रह गई। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात

संबंधों की मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर हुई बात

पेरिस। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के साझा दृष्टिकोण और वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर बात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जनवरी 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की राजकीय यात्रा की थी। इससे पहले जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान 2047 रोडमैप पर चर्चा हुई। यह रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में होगा। उन्होंने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हासिल की गई प्रगति की सराहना की और इसे तेज करने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष

दोनों नेताओं ने वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच लंबे और स्थायी जुड़ाव को याद करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2026 से नई दिल्ली में होने वाले भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का लोगो लॉन्च करके भव्य उद्घाटन की घोषणा की।

यूक्रेन-रूस युद्ध पर हुई बात

दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की। इसमें पश्चिम एशिया और यूक्रेन में युद्ध भी शामिल है। वे नियमित आधार पर समन्वय और निकटता से जुड़े रहने के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमत हुए। पीएम मोदी और मैक्रों ने सीमा पार आतंकवाद सहित

सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को फंडिंग, योजना, समर्थन या अंजाम देते हैं। नेताओं ने सभी आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध समूहों से जुड़े व्यक्तियों को नामित करना भी शामिल है। दोनों पक्षों ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों के अनुरूप धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। दोनों देशों ने नो मनी फॉर टेरर (हस्न्नञ्ज) और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर सहमति

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर भारत-फ्रांस का रोडमैप लॉन्च किया। यह सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है। उन्होंने फ्रेंच स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में भारतीय स्टार्टअप को शामिल करने का स्वागत किया। उन्होंने फ्रांस में भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करने की विस्तारित संभावनाओं का भी स्वागत किया। दोनों नेताओं ने साइबरस्पेस के रणनीतिक महत्व और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग और साइबरस्पेस में जिम्मेदार राज्य व्यवहार के लिए ढांचे के कार्यान्वयन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में अपने समन्वय को मजबूत करने की अपनी इच्छा को दोहराया। साथ ही दुर्भावनापूर्ण साइबर उपकरणों और प्रथाओं के प्रसार से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने 2025 में होने वाले अगले भारत-फ्रांस रणनीतिक साइबर सुरक्षा और साइबर कूटनीति वार्ता की प्रतीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति विमान में पेरिस से मार्सिले के लिए एक साथ उड़ान भरी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और प्रमुख वैश्विक, क्षेत्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम पर चर्चा की। इसके बाद मार्सिले पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो पिछले 25 वर्षों में लगातार एक बहुआयामी संबंध में विकसित हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी और मैक्रों ने एआई पर बात की। अगले वर्ष 2026 को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति बनी है। नेताओं ने यूरोप, पश्चिम एशिया, इंडो-पैसिफिक में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा की।

ईवीएम की सुरक्षा के लिए तहसीलदार ने दीवार में चुनवाया

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं।अब इंतजार रिजल्ट का है। रिजल्ट से पहले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया।इसी दौरान बेमेतरा में अनोखा नजारा देखने को मिला। जहां देर रात तक ईवीएम स्ट्रांग रुम तक पहुंची। जिसके बाद ईवीएम को तहसीलदार ने नवागढ़ के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखवाया।इसके बाद स्ट्रांग रूम के मुख्य गेट में दीवार उठाकर ईवीएम को चुनवा दिया गया।ताकि किसी भी तरह के टेंपरिंग के आरोपों से बचा जा सके।

बेमेतरा जिले के निकाय चुनाव में मुगल-ए-आजम की अनारकली को दीवार में चुनवाने की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं है। नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे को ईवीएम की सुरखा को लेकर काफी चिंता थी।लिहाजा इस चिंता को दूर करने के लिए तहसीलदार ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के बाद मुख्य गेट पर दीवार बनवा दी। इसके बाद ग्रिल से रूम को लॉक करके सुरक्षा के लिए जवान तैनात कर दिए गए।

बेमेतरा जिले मे मतदान का कुल प्रतिशत 77.44% रहा, जो कि मतदाताओं के भारी उत्साह को दर्शाता है। कुल 58,163 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिनमें 28,747 पुरुष और 29,416 महिलाएं शामिल थीं। निकायवार मतदान प्रतिशत अंतर्गत नगर पालिका बेमेतरा मे 71.68%, बेरला में 79.52%, साजा में 75.61%, थानखम्हरिया में 78.46%, देवकर में 79.42%, परपोड़ी में 86.95%, नवागढ़ में 75.66%, दाढ़ी में 83.25%, भिंभौरी में 89.18% और सबसे अधिक कुसमी में 90.90% मतदान हुआ।

धमतरी में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं का बवाल

धमतरी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए 11 फरवरी को मतदान हुआ। अब सभी ईवीएम को स्ट्रांग रुम में रखा गया है। धमतरी में भी पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रुम बनाया गया है। यहां 4 कमरों में सील बंद कर ईवीएम को रखा गया है। आज कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया।

कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और कैमरा को लेकर सवाल उठाए हैं। 4 कैमरे में से 3 कैमरे पर टाइम लेप्स का आरोप है। वहीं टाइम से 2 घंटे पीछे चलने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

भोजराज नाग का टीआई से दुर्व्यवहार मामला : थाने पहुंचे पुलिस परिवार के सदस्य

भानुप्रतापपुर। कांकेर के भाजपा सांसद भोजराज नाग का इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सयुंक्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान के नेतृत्व में पुलिस परिवार के सदस्य भानुप्रतापपुर थाना पहुंचे और सांसद भोजराज नाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया।

इस घटना पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने कहा है कि सांसद नाग थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख से अभद्र व्यवहार को लेकर माफी मांगे। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी करेंगे।

बता दें कि सांसद भोजराज नाग कुछ दिन पहले अंतागढ़ से भानुप्रतापपुर आ रहे थे। इस दौरान नो एंट्री के चलते सांसद की कार घंटेभर जाम में फंस गई। इसके बाद सांसद तमतमाते हुए ञ्रद्ध को जमकर सुनाने लगे। टीआई को खरी खोटी सुनाते हुए सांसद ने कहा कि इस प्रकार का नाटक कर रहे हो, वसूलने में लगे रहते हो। क्या नो एंट्री है, वीआईपी गाड़ी जा रहा है। तमाशा बनाकर रखे हो, बत्तमीज कहीं के, फिर थाने पहुंचकर टीआई के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। सांसद भोजराज ने टीआई पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

ओबीसी आरक्षण मामले में शासन को मिला समय

बिलासपुर। नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण में कटौती को लेकर दाखिल चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अपना पक्ष रखने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी।

याचिकाकर्ता देव सिंह सेठिया ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत घटाने के शासन के अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी है। अब यह अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दास ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243-जेडजी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। इस पर याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रजनी सोरेन और लवकुश साहू ने प्रतिवाद किया कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अन्य संवैधानिक मुद्दों पर राज्य सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को भी जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है।

रेलवे ने माल-भाडा आय में कीर्तिमान स्थापित किया

बिलासपुर/रायपुर। देश की आर्थिक प्रगति में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी स्थापना के बाद से ही देश में औद्योगिक संरचना एवं उनके विकास के लिए कच्चे माल, अयस्कों एवं तापघरों के लिए कोयला पहुचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर रूप से कार्यरत है, ताकि देश में औद्योगिक उत्पादन सुचारु रूप से चलता रहे एवं जनमानस को भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

उल्लेखनीय है कि पूरे देश के पावरहाऊस, उद्योगों / कारखानों को कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, मैंगनीज इत्यादि सामाग्री पहुचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिर्फ 316 दिनों (10.02.2025 तक) में ही 25000 करोड से अधिक आय मालभाडा से अर्जित कर कीर्तिमान कर अपने पहले स्थान को कायम रखा। पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षो से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 25000 करोड से अधिक की मालभाडा आय अर्जित करने वाला रेलवे है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 19 दिन पहले और 2022-23 की तुलना में 31 दिन पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि की तुलना में 6.76त्नअधिक है, जो कि अन्य रेलवे की तुलना में रू.1587 करोड के वृद्धि के साथ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला रेलवे है। पूरे भारतीय रेलवे के मालभाडा आय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का योगदान 17.20 प्रतिशत योगदान है।

देश के औद्योगिक विकास में योगदान देते हुए, महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के कुशल मार्गदर्शन में दक्षिण पूर्ण मध्य रेलवे द्वारा माल लदान के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा माल लदान में नए कीर्तिमान को जल्द ही हासिल कर ली जाएगी।

महाकुंभ मेले के लिए दपूमरे का स्पेशल ट्रेनों की सुविधा

रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद ने मीडिया को संबोधित किया उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से महाकुंभ मेले के दौरान 97 (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 35 फेरे के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए लगातार सभी प्लेटफार्म एवं स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रयागराज स्टेशनों के प्राप्त वीडियो मीडिया के साथ साझा किए। उन्होने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुखद रहे। महाकुंभ के दौरान रेलवे के दौरान 3000 स्पेशल गाडियाँ सहित 13000 से अधिक रेल गाडियाँ चलायी जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण रेलवे से चलाने वाली पाँच महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, बालाघाट एवं नैनपुर होकर परिचालन किया जा रहा है।

महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़-भाड़ के दौरान रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ/सीट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा महाकुंभ मेले के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से एवं होकर 97 (एसईसी से 35 फेरे) फेरे के लिए स्पेशल ट्रेने चलाने की योजना बना गयी है। जिसमे से अब तक 59 फेरे चल चुकी है। इन स्पेशल ट्रेनों से कुम्भ मेला के लिए रेल यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म सीट की सुविधा अधिकाधिक मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ाई 25 लाख की शराब

रायपुर/कवर्धा। आचार संहिता के तहत अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी विभाग, कबीरधाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से लाई जा रही 25 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

विभाग के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम राजवीर सिंह पिता घनश्याम सिंह यादव, निवासी शिवपुरी (मप्र) है। आरोपी को आबकारी जांच चौकी चिल्फी के पास से गिरफ्तार किया गया है।विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से 330 पेटी (16500 नग पाव) देशी मदिरा प्लेन और 200 पेटी (10000 नग पाव) गोवा स्पेशल व्हिस्की कुल 4770 बल्क लीटर मदिरा 25।05 लाख रुपये बताई जा रही है।

आरोपी के पास से ट्रक आरजे 11 जीसी 2927 भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रूपए आंकी गई है, कुल जब्ती 45 लाख रूपए की बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 36, 59(क) के तहत जब्त की गई है।

आबकारी सचिव एवं आयुक्त श्रीमती आर। संगीता, प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल श्याम लाल धावड़े, कलेक्टर कबीरधाम गोपाल वर्मा एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग के जी।के। भगत के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई का नेतृत्व वृत्त प्रभारी बोड़ला अभिनव कुमार रायजादा ने किया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक गीता साहू, अभिनव आनंद बख्शी, रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, भानुप्रताप चौहान, आरक्षक कमल मेश्राम, अमर पिल्ले, इम्तियाज खान, जगदीश सिंह उईके, वाहन चालक डायमंड साहू एवं आबकारी जांच चौकी में तैनात सुरक्षा कर्मियों का विशेष योगदान रहा।

महिला डॉक्टर ने एचओडी पर लगाया मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप

बिलासपुर। सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) की एक महिला डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. पंकज टेंभुर्णिकर पर मानसिक और शारीरिक उत्पीडन् का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते आठ महीनों से उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था। मामले की शिकायत पहले सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति से की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।सिम्स के डीन डॉ. रणमेश मूर्ति ने कहा कि शिकायत की जांच जारी है। मेडिसिन एचओडी को परीक्षा कार्य से अलग कर दिया गया है, उचित निर्णय लिया जाएगा।

महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि डॉ. टेंभुर्णिकर कार्यस्थल पर अनुचित वार्तालाप करने के साथ ही छेड़छाड़ भी करते थे। ड्यूटी के दौरान उन्होंने उसका मोबाइल पटककर तोड़ दिया था, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गई। शिकायत के बाद सिम्स प्रशासन ने डॉ. टेंभुर्णिकर को 6 फरवरी से परीक्षा कार्य से अलग कर दिया। हालांकि, डॉक्टर्स फेडरेशन का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

इस मामले में डॉ. टेंभुर्णिकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 4 फरवरी को मेल मेडिकल वार्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर को मरीज से जबरन 2200 रुपये की दवाएं बाहर से मंगवाने के लिए कहते हुए पकड़ा था। इस पर मरीज के परिजनों ने लिखित शिकायत भी दी थी। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी तीन बार इस तरह की हरकतों पर मौखिक चेतावनी दी जा चुकी थी। डॉ. टेंभुर्णिकर ने महिला डॉक्टर पर जातिगत टिप्पणी करने और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने कोतवाली थाना और महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री से उचित कार्रवाई की मांग की है।

इससे पहले भी सर्जरी विभाग के डॉक्टर ओपी राज पर एक महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसे देखते हुए डॉक्टर्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर संस्थान में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे कानूनी कार्रवाई करने और आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

माघ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई डुबकी

राजिम। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम में बुधवार को राजिम कुंभ कल्प 2025 का शुभारंभ हुआ। वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महानदी में स्नान कर श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और कुलेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। बता दें कि 20 साल बाद मेला स्थल को बदला गया है। मेला अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लग रहा, जहां 54 एकड़ भूमि पर भव्य मंच तैयार किया गया है। इस वर्ष मेले की थीम पंचकोशी धाम पर आधारित होगी, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और संस्कृति का भव्य अनुभव प्रदान करेगी। इस आयोजन के तहत धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, संत समागम और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी को होगा। इसके साथ ही 21 फरवरी से 26 फरवरी तक विराट संत समागम होगा।

जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली हाथी के हमले से फिर ग्रामीण की मौत हो गई। बुधवार की सुबह जंगल में ग्रामीण लाश मिलने के बाद वन विभाग की मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला रायगढ़ वन मंडल का है। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौद निवासी बंधन राठिया 50 साल कल सुबह किसी काम की सिलसिले में जंगल गया हुआ था। इसी बीच जंगल में विचरण कर रहे एक हाथी ने ग्रामीण पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव के ग्रामीणों को बुधवार की सुबह उस समय इस घटना की जानकारी हुई जब बंधन के देर रात तक घर नहीं लौटने के बाद गाँव के ग्रामीणों के अलावा परिजन उसे ढूंढ़ते हुए जंगल पहुंचे तों जंगल में ग्रामीण की लाश पड़ी हुई मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं। बताया जा रहा की वन विभाग के अनुसार धरमजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों जहाँ 91 हाथी हैं।

ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत

जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के कसोली गाँव के पास एक तेज रफ्तार ऑटो व बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, इस घटना में ऑटो में सवार जहाँ एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वही इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले की जानकारी देते हुए गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि गुटपाल में चल रहे मेले को देखने के लिए गीदम से ग्रामीणों के द्वारा एक ऑटो में 10 लोग सवार होकर मेला देखने के लिए गए हुए थे, जहाँ से देर शाम ऑटो से वापस घर लौटने के दौरान कसोली के पास एक तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई, इस घटना में जहाँ ऑटो में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर चोट आई, घटना की जानकारी लगते ही सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से 1 का उपचार गीदम में चल रहा है, तो वही 2 ग्रामीणों को दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया है, जबकि 1 की खराब हालत को देखते हुए उसे मेकाज रेफर कर दिया गया है।

प्रगतिनगर नए पुल के पास घर में घुसा भारी वाहन

कोरबा। कोरबा में प्रगति नगर-कोरबा मार्ग पर फ्लाई ऐश कैप्सूल वाहन सड़क के किनार एक घर में जा घुसा। घटना के कुछ देर में पुलिस की टीम यहां पहुंची। उसने चालक को अपने कब्जे में लिया। दर्री क्षेत्र में हसदेव नदी पर निर्मित नए पुल के पास मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई है। खबर के अनुसार फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट में लगा एक कैप्सूल वाहन इस क्षेत्र से गुजर रहा था। इस दरम्यान चालक का स्टेयरिंग पर से नियंत्रण कमजोर हुआ और वाहन सड़क से उतरकर एक कच्चे मकान में जा घुसा। पड़ोस की महिला ने बताया कि आसपास के लोगों ने आवाज सुनी तो भाग कर मौके पर पहुचे। इन्हीं में से किसी ने पुलिस को जानकारी दी। कुछ देर में पुलिस कर्मी यहां आए और वाहन चालक को अपने कब्जे में लिया। पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन ने जिस मकान को अपनी चपेट में लिया है, घटना के दौरान उसमें कोई नहीं था वरना लेने के देने पड़ जाते। बताया जा रहा है कि घर पर रखे टीवी फ्रिज कूलर अलमारी के अलावा खाद्य सामग्री क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे लाखों का नुकसान हुआ है।

लॉक तोड़कर वाहन ले जा रहा था शातिर चोर

जगदलपुर। जगदलपुर, मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सुरक्षाकर्मी की सूझबूझ से एक चोर को पकड़ा गया। चोर हॉस्पिटल में एक युवक की बाइक को चोरी करके ले जा रहा था। आरोपी को पकड़कर परपा पुलिस को सौप दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोंडागांव निवासी युवक उपेंद्र कोर्राम 26 वर्ष ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके भाई का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे मेकाज में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके भाई ने वहां से उसे डिस्चार्ज कराते हुए जगदलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के चलते वह मेकाज आया हुआ था, जहां से वापस जाने के दौरान उसकी वाहन के पास पहुंचा तो देखा कि सुरक्षाकर्मी उमेश कुमार नागेश ने डिमरापाल निवासी एक युवक सूरज भारती 25 वर्ष को पकड़ा हुआ था। जिसके द्वारा उपेंद्र की गाड़ी का तार को काटकर उसे अन्य तारों से जोड़कर चोरी करने का प्रयास कर रहा थ। जिसके बाद उसे पकड़कर मेकाज चौकी में सौंप दिया गया। जहां से उसे परपा पुलिस को सौंप दिया गया।

मुठभेड़ में घायल जवानों से मिले गृह मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 9 फरवरी को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए जवानों से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मिले। गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों का हाल जाना और उनके अदम्य साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है।

उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक रही है। जिस क्षेत्र को नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वहां हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए थे।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में 47 फीसदी की गिरावट, लोकसभा में सरकार का दावा

रायपुर। मंगलवार को लोकसभा में सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2010 की तुलना में 2024 के दौरान नक्सली हिंसा की घटनाओं में 47 प्रतिशत की कमी आई है। इसके साथ ही आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौत में भी 64 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

एक सवाल के जवाब में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2024 में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) हिंसा के 267 मामले दर्ज किए गए। जबकि 2010 में 499 मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौतों में भी 2010 की तुलना में 64 प्रतिशत की गिरावट आई है। साल 2010 में 343 मौतों की तुलना में साल 2024 में 122 मौतें दर्ज की गई।

राय ने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) राहत और पुनर्वास योजना के तहत सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को जारी किए गए 1925.83 करोड़ रुपये में से राज्य को 43 प्रतिशत ज्यादा मिला। यानी छत्तीसगढ़ को 829.80 करोड़ रुपये दिए गए। जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में कमी आई।

एसआरई योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को वामपंथी हिंसा में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग और नक्सली हिंसा में संपत्तियों के नुकसान के लिए सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों को मुआवजे के प्रावधानों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए धन देती है।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले पांच साल के दौरान विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को जारी किए गए कुल 394.31 करोड़ रुपये में से छत्तीसगढ़ को 21.6 प्रतिशत राशि मिली। इस योजना का उद्देश्य विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं (एसआईबी) और जिला पुलिस को मजबूत करना है। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 85.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 147 सहित सात सौ दो फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन (एफपीएस) स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 125 सहित 612 एफपीएस का निर्माण किया गया है।

अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में विकास को और गति देने के लिए, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत राज्यों को राशि दी जाती है। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों (2019-20 से आज तक) के दौरान सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 2384.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 773.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत, पिछले पांच साल में (2019-20 से आज तक) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 654.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से बॉडी बिल्डर्स चैम्पियनशिप के विजेता खिलाड़ियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से बुधवार

को यहां राजभवन में बॉडी बिल्डर्स के विश्व तथा एशिया चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की। बॉडी बिल्डर्स के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अंबिकापुर के अशोक बेहरा ने स्वर्ण पदक, साउथ एशिया चैम्पियनशिप में बिलासपुर के आनंद राव ने रजत पदक प्राप्त किया। इसी तरह दिव्यांग खिलाड़ी राजनांदगांव के महेन्द्र यदु और रायपुर के श्री ई.शिवा मिस्टर छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता के विजेता बने। राज्यपाल डेका ने इन सभी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की और आगे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश एवं देश का नाम रौशन करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के पदाधिकारी अभिषेक वर्मा, अरविन्द सिंह, महेन्द्र तेकाम और राजशेखर राव उपस्थित थे। उन्होंने डेका को आगामी माह बिलासपुर में आयोजित होने वाले जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित भी किया।

पूर्व महापौर एजाज ढेबर से शराब घोटाले मामले में पूछताछ

रायपुर। शराब घोटाले के मामले में समन पर पूर्व महापौर एजाज ढेबर बुधवार को दोपहर ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे। ब्यूरो उनसे घोटाले से संबंधित कुछ मामलों में पूछताछ कर रहा है। एजाज के साथ उनके वकील भी है। खबर है कि एजाज के बड़े भाई अख्तर ढेबर और कुछ रिश्तेदार को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें शराब घोटाले मामले को लेकर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर पहले से ही जेल में बंद है। दरअसल, 7 फरवरी को ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर एजाज को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, लेकिन निगम चुनाव के कार्यों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए समय मांगा था। निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अब वह पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय पर पहुंचें हैं।

शराब घोटाला मामले में अरुणपति त्रिपाठी को मिली सुको से जमानत

रायपुर। कथित शराब घोटाले के आरोपी

अरुणपति त्रिपाठी को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन फिर भी वे जेल के अंदर ही रहेंगे क्योंकि ईओडब्ल्यू में अभी एक और मामला चल रहा है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अरुणपति त्रिपाठी जगदलपुर के जेल में बंद है। अरुणपति के खिलाफ झारखंड में भी शराब घोटाले का आरोप है। त्रिपाठी के खिलाफ ईडी और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। अरुणपति त्रिपाठी भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनके आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहने के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का दावा किया गया है।

माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने खारुन नदी में किया स्नान

रायपुर। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा महादेवघाट स्थित खारुन नदी में देखने को मिला जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालु खारुन नदी में स्नान किया। पूरे घाट पर जयकारों और मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रहा था जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। महादेवघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।

13 व 14 को टाटानगर- इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी

रायपुर। चकरधरपुर रेलवे मंडल के बन्डामुन्डा रेलवे स्टेशन में अधोसंरचना कार्य के लिए ब्लॉक लिया जायेगा। यह कार्य 13 एवं 14 फरवरी को लिया जायेगा। जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबन्धित गाड़ी संख्या 18109/18110 टाटानगर-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

राजधानी में हवाई फायरिंग करने वाले अज्ञात दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस के कार्रवाई के बाद भी गुंडे-बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर में पिस्टल से हवाई फायरिंग करने वाले दो आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। दरअसल, राजधानी में अज्ञात बदमाशों ने अपने पास रखे पिस्टल से फायरिंग कर दी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि बीते रविवार को रात साढ़े 12 बजे थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत गोलाबाजार स्थित मटका लाइन में कुछ असामाजिक तत्वों ने पिस्टल से हवाई फायरिंग की गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मामले में एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की 10 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों की पहचान तैफुद्दीन उर्फ टप्पू और मोहम्मद कलीम के रूप में की।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने गिनाए केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मिलने वाले फायदे

■ इनकम टैक्स में कटौती का 12 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ

रायपुर। मोदी सरकार के केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देने रायपुर आए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे छत्तीसगढ़ को होने वाले फायदों को एक-एक कर गिनाए। उन्होंने बताया कि एक तरफ इनकम टैक्स में कटौती से प्रदेश के 12 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए दो करोड़ का टर्म लोन देने के साथ कौशल विकास योजना से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री दयाल दास बघेल के साथ केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत करना है। भारत में मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके साथ बजट का सरलीकरण हो रहा है, जिसे कल हम लोकसभा में पेश करेंगे।

उन्होंने कहा कि युवा का समर्थ बढ़ाने के लिए हमारे देश में आज तक रिसर्च के लिए बहुत कम ध्यान दिया है। रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बल दे रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है। ये सब देखने के लिए स्टार्टअप 10 हजार करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। 2014 से पहले यह बहुत कम था।

जोशी ने कहा कि इनकम टैक्स के साथ-साथ अन्य स्लैब भी हमने बहुत कम किया है। 12 लाख के साथ-साथ 18 लाख रुपए की इनकम वालों का भी 17 हजार रुपए कम हो रहा है। एक समय था, जब एक मिडिल क्लास परिवार के लिए डॉक्टर बनना संभव ही नहीं था। हमने पिछले पांच सालों में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के परिवार के सपनों को साकार करने का कार्य किया है।

प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च का जिक्र करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि 20 हज़ार करोड़ और साइंटिफिक सेक्टर में रिसर्च के लिए 10 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट किया है। हम बहुत बड़ा फंड तैयार कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड के लिए कई वायरस जैसे कोविड व अन्य पर रिसर्च के लिए बड़ा फंड जारी किया है।

उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी वालों के लिए स्वास्थ बीमा देने का काम किया है। सामान्य आदमी सोचता है, पैसा नहीं है, स्टार्टअप नहीं करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भी हमने तैयारी की है। इंडियन लैदर को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इंडियन इंफ्रास्ट्रचर डेवलप करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए दो करोड़ का टर्मलोन की तैयारी की है। बिजनेस शुरू करने के लिए पांच लाख महिलाओं को 2 करोड़ का टर्मलोन दिया जाएगा। जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। किसान क्रेडिट कार्ड को 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि रेलवे के बारे में बात की जाए तो, टोटल 2025-26 में 6 हज़ार 925 करोड़ से अधिक दिया गया है। इसमें रेलवे के आधुनिकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर्यटन क्षेत्र में पचास हज़ार रोजगार देने का बजट तैयार किया है। जिससे हर प्रदेश में पर्यटन को विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए योजना तैयार किया गया है।

मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की संभावना है, जिसका आदिवासियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचों के लिए तैयारी की गई है। इससे सभी आदिवासियों को बड़ा फायदा होने वाला है। हमने अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बजट तैयार किया है।

वित्त मंत्री चौधरी की बजट प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री वर्मा के साथ चर्चा

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री टंक राम वर्मा के साथ उनके विभागों राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण से सम्बंधित 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद के प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की। इस मौके पर वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित राजस्व एवं खेल विभाग और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

वित्त मंत्री ने किया मंत्री नेताम के बजट प्रस्ताव पर चर्चा

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्री रामविचार नेताम के साथ बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री स्तरीय चर्चा में मंत्री नेताम के विभाग आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण से संबंधित वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा की। इस मौके वित्त विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल एवं कृषि, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

कुकरेजा की कांग्रेस वापसी पर जुनेजा ने खरीद-फरोख्त की ओर किया इशारा

रायपुर। निष्कासित कांग्रेस नेताओं की पार्टी में वापसी को लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है। अजीत कुकरेजा का नाम भी सूची में आने के बाद रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में पैसे लेकर कुकरेजा की पार्टी में वापसी की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं।

दरअसल अजीत कुकरेजा की पार्टी में वापसी का जुनेजा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर पहले ही विरोध किया था। पत्र में उन्होंने कुकरेजा पर पार्टी को हराने के लिए उनके क्षेत्र में षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था। मंगलवार देर शाम कांग्रेस

ने कई जिलों से निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल करने की सूची जारी की। इसमें रायपुर से अजीत कुकरेजा का भी नाम शामिल है। सूची आने के बाद कुलदीप जुनेजा ने कहा है कि 15 फरवरी के बाद बहुत कुछ बोलूंगा। फिलहाल शायरी के जरिए इतना ही कहूंगा कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुद की कसम खुदा से कम नहीं।

पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 15 तारीख के बाद खुलकर बोलूंगा। अभी बस दो लाइन बोलकर समझाता हूं कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम नहीं। रायपुर में सबसे कम मतदान को लेकर उन्होंने कहा, ये सरकार और निर्वाचन आयोग की लापरवाही है। कल लोग मतदाता पर्ची को लेकर दिनभर भटकते रहे। ये लापरवाही है। जो जनता वोट देना चाहती थी वो भी वोट नहीं दे सकी। अगर ये समस्या नहीं होती तो 70त्न से अधिक वोटिंग होती। पूर्व महापौर एजाज ढेबर को ईओडब्ल्यू की नोटिस पर कुलदीप जुनेजा ने कहा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कांग्रेस को बस परेशान करने का काम कर रही है। ये भी उसी का उदाहरण है। निकाय चुनाव में रायपुर के नतीजे को लेकर जुनेजा असमंजस में दिखे।

भैरमगढ़ ब्लॉक के 12 पंचायतों में सरपंच व 574 वार्डों के पंच निर्विरोध चुने गये

बीजापुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम वापसी के बाद भैरमगढ़ ब्लॉक के 12 पंचायतों में सरपंच व 574 वार्ड पंच के पदों में निर्विरोध चुनाव हुआ है। भैरमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीआर. साहू ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन व नाम वापसी के बाद जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत आने वाली 12 ग्राम पंचायतों में मर्रामेटा, टिन्डोडी, इतामपार, बैल, हुर्रागुवाली, जैगुर, कोडरोंजी, पोटेनार, फोल्होड, कोतरापाल, मदपाल व बेचापाल के ग्रामीणों ने बैठकर सभी वार्डो के लिए एक-एक पंच व एक सरपंच का नामांकन दाखिल कराया। जिससे निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बनी और निर्विरिध चुनाव हो गया।

सीईओ साहू ने ग्रामीण की इस सूझबूझ व एकता की सराहना करते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सीईओ पीआर साहू के मुताबिक भैरमगढ़ पंचायत के अंतर्गत आने वाली कुल 60 ग्राम पंचायतों में से 12 पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन के बाद बची 48 पंचायतों में

सरपंच के लिए 145 प्रत्याशी तथा 749 वार्डों में से 574 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन के बाद बचे 175 वार्डों में 370 उम्मीदवारों के लिए मतदान होगा। उन्होंने आगे बताया कि जनपद के 15 क्षेत्रों में कुल 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर कर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भैरमगढ़ एसडीएम विकास सर्वे व सीईओ पीआर साहू ने सभी अभ्यर्थियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण व शालीनता से निर्वाचन में भाग लेने का आग्रह किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में क्रमशः 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। मतदान के बाद मतों की गणना क्रमशः 18, 21 और 24 फरवरी को होगी।

मुठभेड़ में घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम शर्मा

डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश

रायपुर। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए थे। इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल भी हुए थे।

आज उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुँचे। उन्होंने जवानों का हाल जाना और उनके अदम्य साहस की सराहना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि सरकार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुठभेड़ नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक रही है। जिस क्षेत्र को नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, वहां हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाते हुए भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रयागराज जाना पड़ा भारी, नगदी समेत सोने के जेवरात पार

रायपुर। कुकुरबेडा में रहने वाले एक परिवार को प्रयागराज महाकुंभ में जाना महंगा पड़ा गया और जब वे वापस घर लौटे तो नगद 70 हजार रुपये सहित आलमारी में रखे सोन का 3 मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, 1 जोडी कान का झुमका, टाप्स, गले का नेकलेस, चैन, चांदी का पायल, कांसे का सामान गायब था। सरस्वती नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी खोजबीन में जुट गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुकुरबेडा आमानाका निवासी नंदा तिवारी ने मंगलवार की शाम सरस्वती नगर थाने में चोरी का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि वे 7 फरवरी की रात 10 बजे घर में ताला लगाकर परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ गए थे जहां से वे तीन दिन बाद 10 की सुबह घर वापस आए तो देखा की घर के अंदर हाल के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और सभी कमरों का सामान बिखरा हुआ है। कमरे में रखा स्टील का आलमारी टुटा हुआ था जिसमें रखे सोन का 3 मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, 1 जोडी कान का झुमका, टाप्स, गले का नेकलेस, चैन, चांदी का पायल, कांसे का सामान नगदी 70,000 रूपए गायब थे। उसे 7 से 10

के बीच कोई अज्ञात चोर सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए।

पुजारी के मकान में चोर ने किया हाथ साफ

पुजारी महेंद्र तिवारी को घर में ताला लगाकर सरोना स्थित इंद्रप्रस्थ पूजा कार्यक्रम में जाना महंगा पड़ा गया और अज्ञात चोर ने मेन गेट का ताला तोडकर जेवर, नगदी 70 हजार रुपये सहित कुल 1 लाख 15 हजार रुपये के समान पर हाथ साफ कर छत के रास्ते भाग निकला। पुरानी बस्ती इलाके के खल्लारी नगर भाठागांव के पुजारी महेंद्र तिवारी रविवार की शाम को परिवार सहित इन्द्रप्रस्थ सरोना पूजा कार्यक्रम में गये थे। 11 की सुबह पड़ोसी ने फोन कर जानकारी दी की उसके घर में चोर लोग घुसे हैं। मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और चोर छत के रास्त भाग गए। महेंद तिवारी ने घर आकर देखे तो मेन दरवाजा एवं अंदर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखे तो आलमारी खुला था जिसमें रखे सोने चांदी के जेवर नेकलेस, टाप्स, मंगलसूत्र नगदी 70,000 रूपये कुल 1,15,000 के सामान गायब थे। पुरानी बस्ती पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन में जुट गई है।

घर के सामने गांजा पीने से रोका तो फोड़ा सिर

रायपुर। घर के सामने गांजा पीने से मना करने पर मनीष महरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर श्रीलंकापारा चंदनडीह निवासी भोपाल मिश्रा को जान से मारने की धमकी देकर हाथ में पहने कड़ा से हमला कर सिर को फोड़ दिया। आमानाका पुलिस ने शिकायत पर मनीष महरा और उसके साथियों के खिलाफ 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

भोपाल ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि कल रात मोहल्ले का मनीष महरा अपने साथियों के साथ घर के सामने आकर गंजा पी रहे थे। उसके मना करने पर वे लड़के भड़क गए और तू कौन होता है मना करने वाला कहकर अपने हाथ में पहने कड़ा से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में भोपाल मिश्रा के सिर में चोट आई है।

महाकुंभ और सरकारी निमंत्रण

सरकारी खर्च से दान-पुण्य नहीं करना चाहिए, जिन्हें जाना है वो स्वतंत्र : भूपेश

रायपुर। सरकारी खर्च पर दान-पुण्य नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा, पूजा, अर्चना, दान-पुण्य में सारा खर्च आपका अपना स्वयं का होना चाहिए। गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व मन साफ होना चाहिए। दूषित मन के साथ डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलेगा। ये बातें सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ जाने के सवाल पर बघेल ने कहा कि जिन्हें जाना है वे स्वतंत्र हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं, जिनकी इच्छा होगी वो जरूर महाकुंभ जाएंगे।

दअरसल साय सरकार की ओर से सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को महाकुंभ जाने के लिए सरकारी निमंत्रण दिया गया है। इस पर भूपेश बघेल ने महाकुंभ के बहाने साय सरकार के साथ योगी सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रचार के उद्देश्य से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसी वजह से योगी कैबिनेट की बैठक की जा रही और 12 बार दौरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा

कि सरकार हमेशा से कुंभ का आयोजन करते नहीं आई है। यदि सरकार की ओर से आयोजन है तो सिर्फ प्रचार करना नहीं, व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है। भूपेश बघेल ने योगी सरकार की खराब व्यवस्था को भगदड़ का कारण कारण बताया।बघेल ने कहा, भगदड़ के बाद बुलडोजर से सभी की चीजों को उठाया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 15 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन कुंभ में कितने बिछड़े, कितने घायल हुए, कितनी मौतें हुई, ये अकड़े अब तक नहीं बताए हैं।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या धीरेंद्र शास्त्री मोक्ष का मतलब भी समझते हैं। अध्यात्म और धर्म में मोक्ष सबसे उच्च कोटि का शब्द है। जन्मजन्मांतर के कर्मों को भोगने से मिलने वाला मोक्ष किसी को रौंदने से नहीं मिलता।

सनातन में आस्था रखने वाले जाएंगे कुंभ : अरुण साव

वहीं कुंभ स्नान को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण सव ने कहा है कि जो भी सनातन पर आस्था रखते हैं, जिनकी इच्छा होगी वो जरूर महाकुंभ जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने कुंभ स्नान के लिए जाने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ के सभी विधायक-सांसद संयुक्त रूप से स्नान के लिए महाकुंभ जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का जाना पहले ही रद्द

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी विपक्षी विधायकों और सांसद को भी महाकुंभ जाने का न्योता दिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत ने पहले ही मुख्यमंत्री से बातचीत में असमर्थता जताई थी। हालांकि कांग्रेस के सात विधायक भी साय सरकार के साथ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इनमें विद्यावती सिदार, दलेश्वर साहू, व्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, संदीप साहू, इंद्र साव, रामकुमार यादव और राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। बता दें कि कल सुबह 8 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 7 विधायक प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना होंगे।

कार्यालय संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

Email Id: cocghbzone02@gmail.com फोन नं. 0771-4903223

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा, सामान्य आवास योजनातंर्गत कचना, रायपुर में स्थित एम.आई.जी. डीलक्स भवन क्रमांक-28, को इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्रमांक 1079 दि.23.10.2008 के द्वारा श्री शशांक शर्मा पिता स्व. एस.पी. शर्मा, के नाम स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन के मद में सम्पूर्ण राशि जमा कर भवन कि लीजडीड दि. 18.08.2009 को पंजीकृत करने उपरांत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7305 दिनांक 24.08.2011 भवन का आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है।

वर्तमान में आबंटी श्री शशांक शर्मा पिता स्व. एस.पी. शर्मा, निवासी: आजाद चौक रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री विनय कुमार पिता स्व. रामलखन प्रसाद, निवासी नवरंगी स्कूल गौतम नगर जनता रोड़ पटना (बिहार) पिन: 800001 को विक्रय करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: उक्त भवन के विक्रय करने के सबंध में किसी व्यक्ति शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय बैंक अथवा वित्तिय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र-2, शंकर नगर, रायपुर

सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करे आप

विवेक शुक्ला

आम आदमी पार्टी अपने जन्म के बाद से पहली बार विपक्ष की भमिका में नजर आयेगी। दिल्ली में आप की सरकार अरविंद केजरीवाल और फिर कुछ महीने तक आतिशी की सदारत में चली। हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। ऐसे में, उसे विपक्ष में बैठना होगा। आप की पंजाब में भी सरकार है। अब आप को सीखना होगा कि विपक्ष में रहकर किस तरह काम किया जाता है। सरकार चलाना जितना अहम है, विपक्ष में रहकर काम करना उससे कम अहम नहीं। आप के नेताओं का चरित्र अराजकता से भरा है। ये अपनी नयी इबारत गढ़ने की कोशिशें करते हैं। इन्हें समझना होगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका कई तरह से महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, कमियां उजागर करता है और बेहतर विकल्प सुझाता है। इसके साथ ही विपक्ष जनता के मुद्दों, शिकायतों और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखता है, ताकि सरकार उन पर ध्यान दे और उचित कदम उठाये। अरविंद केजरीवाल और आप के बाकी शिखर नेताओं को दिल्ली के 22 विजयी विधायकों को समझाना होगा कि विपक्ष में रहते हुए वे सरकार के काम पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सरकार को जनता के हित में नीतियां बनाने के सुझाव दें। दिल्ली विधानसभा का सत्र कुछ समय बाद शुरू होगा। तब आप के विधायकों पर दिल्ली और देश की निगाहें रहेंगी कि वे किस तरह सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस में भाग लेते हैं, जिससे नीतियों और कानूनों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आप के विधायकों को समझना होगा कि चुनाव हो चुके हैं और सरकार भाजपा की बन रही है। अब उन्हें जिम्मेदार विपक्ष के रूप में काम करना होगा। विपक्ष सरकार के सामने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण और नीतियां प्रदान करता है, जिससे लोगों को चुनाव के समय बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आप की सरकार ने 10 साल के अपने दो कार्यकालों में विपक्षी सदस्यों को कभी उनके अधिकार कायदे से नहीं दिये। यह हालत तब थी, जब 2014 में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के सिर्फ तीन विधायक थे और 2019 में मात्र आठ। दिल्ली विधानसभा में गुजरे दौर में मीर मुश्ताक अहमद, जग प्रवेश चंद्र, राम वीर सिंह विधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता जैसे विपक्षी नेताओं ने शानदार काम किया है। ये सरकार के साथ तालमेल बिठाकर रखते थे। जग प्रवेश चंद्र कहते थे कि एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सरकार को जवाबदेह बनाता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। वह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों का विश्लेषण करता है, उनकी कमियां उजागर करता है, और जनता को उनके संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में सूचित करता है। हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई दूसरे नेता प्रधानमंत्री पर अनाप-शनाप टिप्पणियां करते थे। देश में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली वालों को अपनी हरकतों से लगातार निराश किया। दिल्ली की सियासत में अराजकता लाने का श्रेय आप को ही जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि केजरीवाल और उनके साथी इतने अहंकारी हो जायेंगे। लोकतंत्र में किसी नेता का अहंकारी होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और उनकी जरूरतें पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। अहंकारी नेता तो अक्सर जनता की राय को नजरअंदाज करते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। अफसोस कि आप के कुछ नेताओं में अहंकार की भावना आ गयी थी। उन्हें लगने लगा था कि वे विशेष और दूसरों से बेहतर हैं। केजरीवाल बार-बार कहने लगे थे कि मोदी जी समझ लें कि वे इस जन्म में तो आप को हरा नहीं सकते। आप के साथ एक दिक्कत यह भी हुई कि वहां सब कुछ केजरीवाल के इर्द-गिर्द ही चलता रहा। आप के भीतर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वह अपनी आलोचना नहीं सुनते थे। आप की राजनीति में अराजकता तो शुरू से ही देखी जा रही थी। हद तो तब हो गयी, जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मुख्यमंत्री ने अपने निजी सहायक द्वारा सरकारी आवास बुलाकर गुंडे किस्म के हिस्ट्रीशीटर विधायकों द्वारा लात- घूंसों से पिटाई करवा दी। इस बार दिल्ली की जनता ने उन्हें जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। केजरीवाल और उनके कई करीबी साथियों को हरा दिया। लंबा सत्ता सुख भोगने के बाद अब उन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी।

आखिर दिल्ली में क्यों ढ़हा 'आप' का किला?

योगेश कुमार गोयल

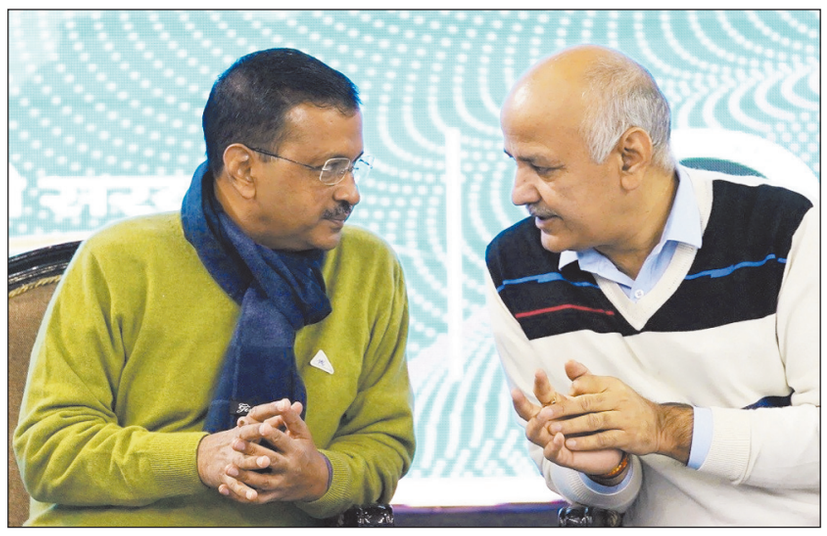

दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला बुरी तरह ढ़ह गया है। आतिशी को छोड़कर पार्टी के लगभग तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए और आप ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी लेकिन 2020 में यह संख्या घटकर 62 रह गई थी। वहीं, भाजपा ने 2015 में मात्र 3 सीटें जीती थी जबकि 2020 में 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी और बंपर जीत के साथ पूरे 27 सालों बाद अब दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हुई है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज आखिरी बार कुल 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और अब 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में बड़ी वापसी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे और यह विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए नाक का बहुत बड़ा सवाल था लेकिन भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे और क्यों पार्टी की राजनीतिक स्थिति इतनी कमजोर हुई?

दिल्ली में आप सरकार ने करीब एक दशक तक शासन किया और लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जनता के बीच असंतोष और बदलाव की इच्छा बढ़ी थी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी और वादों को पूरा न करने के आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं ने विकल्प के रूप में भाजपा की ओर रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने, दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बनाने और साफ पानी उपलब्ध कराने जैसे जो तीन प्रमुख वादे दिल्ली की जनता से किए थे, वे एक दशक में भी पूरे नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह इत्यादि पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाते हुए 'आप' की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को कमजोर किया। इन घटनाओं ने पार्टी की स्वच्छ राजनीति के दावे पर सवाल खड़े किए और जनता के विश्वास को कमजोर किया। खासतौर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाद में उनके इस्तीफे के कारण पार्टी के नेतृत्व में अस्थिरता आई और केजरीवाल की विश्वसनीयता में बड़ी कमी आई। केजरीवाल ने हमेशा से वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए थे लेकिन शीशमहल के मुद्दे पर वे स्वयं 'वीआईपी कल्चर' के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गए थे, भाजपा-कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आप को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन्होंने लग्जरी गाड़ियां तो ली ही, केंद्र से जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की शीर्ष सुरक्षा भी ली।

पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व के मुद्दों ने भी आप की हार में बड़ा योगदान दिया। कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने या निष्क्रिय होने से संगठनात्मक ढ़ांचे में कमजोरी आई। इसके अलावा नेतृत्व के प्रति असंतोष और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मनोबल को प्रभावित किया। आप सरकार ने बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में मुफ्त सेवाओं की घोषणा की थी लेकिन विपक्ष ने इसे 'रेवड़ी संस्कृति' कहकर आलोचना करते हुए इसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया। इसके अलावा, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आई समस्याओं ने जनता के बीच नकारात्मक धारणा बनाई, जिससे 'आप' की लोकप्रियता में गिरावट आई। दिल्ली में सड़क, परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढ़ांचे के विकास में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। इसके अलावा प्रदूषण, जलभराव और कूड़े के ढ़ेर जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने से जनता में केजरीवाल सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी थी। इन मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता ने मतदाताओं को निराश किया। दिल्ली में आप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण मुफ्त बिजली-पानी जैसी योजनाओं को माना जाता रहा लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ने भी 'आप' वाला ही दांव खेला और अपने चुनावी संकल्पों में महिलाओं, बच्चों व युवाओं से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों तक के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो की ही, साथ ही यह ऐलान भी किया कि वह सत्ता मिलने पर आप द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को जारी करेगी। भाजपा की इन घोषणाओं से आप की चुनौती बहुत बढ़ गई थी।

विपक्ष और खासकर भाजपा की मजबूत रणनीति तथा भाजपा का मुखर प्रचार आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। भाजपा ने आप सरकार की तमाम कमजोरियों को उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी इस तरह टिकट बांटे, जिसने कई सीटों पर आप को आसान जीत से रोकने में अहम भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार, विकास की कमी और अन्य मुद्दों पर केंद्रित अभियानों ने जनता के बीच आप के प्रति नकारात्मक धारणा बनाई। भाजपा ने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया, जिससे आप के समर्थन में बड़ी कमी आई। चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चाएं थी लेकिन हरियाणा विधानसभा में दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण दिल्ली में भी दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके चलते विपक्षी मतों का विभाजन हुआ और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने के फैसले ने आप की रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया और विपक्षी एकता की कमी का स्पष्ट संकेत दिया। इसका भी दिल्ली के मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछले दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2015 में कांग्रेस को 9.7 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन 2020 में मतों का प्रतिशत गिरकर महज 4.3 फीसद रह गया था लेकिन इस बार कांग्रेस के मत प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका नुकसान भी आप को भुगतना पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में 'आप' को ऐसी 'आपदा' करार देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भरपूर प्रयास किया, जिसने जनता के फायदे के लिए मिलने वाली केंद्र की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उससे मतदाताओं के बीच आप की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा और प्रधानमंत्री के 'आपदा' वाले नारे से भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ा। दिल्ली की आबादी में पूर्वांचल (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड) से आए लोगों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और विपक्ष ने इस समुदाय की समस्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए आप सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग की समस्या, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देना, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों ने पूर्वांचली समुदाय में असंतोष बढ़ाया। इस उपेक्षा के कारण इस समुदाय का समर्थन आप से हटकर अन्य दलों की ओर गया और इसका नुकसान आप को भुगतना पड़ा।

बहरहाल, केजरीवाल का दावा था कि वे राजनीति में नैतिकता और शुचिता की राजनीति करने आए हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों के चुनावों में जिस तरह से पैसा खर्च किया और दिल्ली में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर जो 'शीशमहल' बनवाया, उसे लेकर उन पर लगातार लगते रहे आरोपों का पार्टी के पास ही कोई कारगर जवाब नहीं था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े-बड़े दावों के बीच शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे, केजरीवाल की तानाशाहीपूर्ण नेतृत्व शैली, उनका अड़ियल रवैया, इस तरह की बातों से मतदाताओं का केजरीवाल से मोहभंग होता गया और भाजपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरती गई। कुल मिलाकर, केजरीवाल की कथनी और करनी के बीच बड़ा अंतर आप की हार का बड़ा कारण रहा। दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों और बारिश के मौसम में जलभराव के मुद्दे ने भी दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस मुद्दे पर आप को घेरा, जिसने आप की लुटिया डुबोने में बड़ी भूमिका निभाई।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

सुतरां वह बैल क्या पदार्थ है, इसका स्पष्टीकरण सुनिये। (1) याज्ञिक लोग कहते हैं कि- यज्ञ ही सर्व कामनाओं का बरसाने वाला या पूरा करने वाला है, अतएव वही वृषभ है। चारों ऋत्विक् उसके सींग = रक्षक स्थानीय हैं, वेदत्रयी (तीनों वेद) ही पाँव हैं, जिनके आधार पर यज्ञ को खड़ा किया जाता है। यजमान और उसकी पत्नी दोनों शिर हैं, गायत्री आदि सातों छन्द: हाथ हैं, जिनके द्वारा समस्त यज्ञकार्य सम्पादन होता है। प्रात: मध्याह्न और सायंकाल के तीनों सवनों से ही वह बन्धा हुआ है। अतएव यह देवों का देव है तथा मनुष्यों द्वारा आचरणीय होने के कारण उनमें प्रवेश करता है।

सायणाचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, कि याज्ञिक अर्थ के अतिरिक्त उक्त सूक्त के अग्नि, सूर्वे, अप, गाय और घृत यह पांच देवता हैं।

तदनुसार इसका अर्थ भी पांचों से सम्बद्ध है। सो (2) अग्निपक्ष में-चारवेद सींग, तीनों सवन पांव, ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य दोनों शिर, सातों छन्द हाथ, मन्त्र, ब्राह्मण विधि और अर्थवाद तीनों से बन्धा हुआ। (3) सूर्य पक्ष में चारों दिशाएं सींग, वेदत्रयी पांव, दिन रात दो शिर, सातों रश्मियें- किरणें हाथ, पृथिवी अन्तरिक्ष और यू: स्थानों में बन्धा हुआ । आदित्याज्जायते वृष्टि: के अनुसार वही वृषभ वर्षा के करने वाला और मेघादि के रूप में गर्जने वाला है।

पतञ्जलि जी अपने व्याकरण-भाष्य में इसका व्याकरणपरक अर्थ करते हैं, यथा- (4) नाम आख्यात उपसर्ग और निपात चारों सींग, भूत भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल पांव, सुबन्त और तिङन्त दो शिर, सातों विभक्तियें हाथ, उर: कण्ठ और शिर तीन स्थानों द्वारा उच्चारित होने के कारण तीन जगह से बन्धा हुआ। वहीं सब कामों को वर्षाने वाला वृषभ है।

क्रमश: ...

देश की आजादी में सरोजिनी नायडू ने निभाई अहम भूमिका

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 13 फरवरी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। वह एक बेहतरीन कवियत्री और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं। सरोजिनी नायडू हमेशा महिला अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करती रहीं। वहीं उनके बर्थडे के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि नायडू के भाषण, सशक्त आवाज और कविता सुनाने के अंदाज से महात्मा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसी कारण महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को देश की नाइटिंगेल का खिताब दिया था। इसके अलावा वह स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहीं।

हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। वह बचपन में बेहद होशियार और कुशाग्र बुद्धि वाली थीं। पढ़ाई-लिखाई में तेज होने के साथ ही उन्होंने छोटी सी उम्र में कविताएं लिखना शुरूकर दिया था। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा बेहद अच्छे नंबरों से पास कर ली थीं। स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह कविताएं भी लिखती थीं। उनकी पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रैशोल्ड था।

आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। एक बार उन्होंने देश के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि देश की महानता, बलिदान और प्रेम देश के आदर्शों पर पूर्ण रूप से निहित है। सरोजिनी नायडू द्वारा किए गए कार्यो और योगदान को ध्यान में रखने हुए उनके जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।

सरोजिनी नायडू ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों की बढ़ चढ़कर वकालत की। देशभर में घूम-घूमकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने का काम किया। वहीं देश को आजादी दिलाने में वह महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। सरोजिनी नायडू के मुताबिक किसी भी देश की स्थिति वहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति को देखकर जाना जा सकता है।

साल 1928 में देश में प्लेग महामारी तेजी से फैली थी। इस दौरान सरोजिनी नायडू ने अपने जान की परवाह किए बिना जागरुकता फैलाने के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की सेवा की। उस दौरान उनके समर्पण और जुनून को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी।

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देश को आजादी दिलाने के लिए हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वह हर महिला के लिए प्रेरणा है।

वैसे तो सरोजिनी नायडू के नाम कई उपलब्धियां हैं लेकिन साहित्यिक योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कुछ कविताएं तो पाठ्यक्रम में शामिल की गईं। क्योंकि वह बहुत ही मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ किया करती थीं, इसी कारण सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। वहीं दिल का दौरा पड़ने से 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू की मृत्यु हो गई।

क्या तानाशाही की राह पर हैं मो यूनुस?

विकास मिश्रा

बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी आशंका पैदा हो रही है कि क्या मो। यूनुस खुद को बांग्लादेश का पहला तानाशाह बनाने के लिए परिस्थितियां और भूमिका तैयार कर रहे हैं? आशंका इसलिए जन्म ले रही है कि वे चुनाव टालने का हर नुस्खा आजमा रहे हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बेवजह की तनातनी इस आशंका को और मजूबत बनाती है। यूनुस चाहते हैं कि विवाद बढ़े और लोगों का ध्यान चुनाव की मांग से भटकाया जा सके। उनकी मंशा को बांग्लादेशी समझने लगे हैं। इसलिए नाराजगी बढ़ रही है।

यूनुस ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद कहा था कि जल्दी ही बांग्लादेश में चुनाव करा लिए जाएंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को यह उम्मीद जगी कि शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद उसका रास्ता साफ है। यूनुस ने उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया लेकिन कुछ ही दिनों बाद गंभीर बीमारी की वजह से वे लंदन चली गईं। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वे लंदन से लौटेंगी?

क्या राजनीति में सक्रिय होंगी? यदि वे नहीं लौटती हैं तो इसका मतलब है कि यूनुस के लिए मैदान खाली है। दो कद्दावर नेताओं में से कोई भी उन्हें चुनौती देने के लिए अब मौजूद नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि वे चुनाव होने ही नहीं देना चाहते हैं। शेख हसीना की पार्टी को उन्होंने तबाह कर दिया है। इधर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हालांकि लगातार मांग कर रही है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं लेकिन यूनुस बहाने बना रहे हैं। अब उन्होंने और उनके लोगों ने एक नया पेंच डाल दिया कि मतदान की उम्र को 18 साल से घटाकर 17 साल किया जाना चाहिए।

इसका मतलब है कि नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जाएगी और फिर चुनाव की बात आएगी। इसमें अगले कई साल लग सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मतदान के लिए उम्र कम करने का विरोध किया है। माना यह जा रहा है कि यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद यह तय कर लिया था कि फिलहाल चुनाव नहीं कराना है।

राजनीति में उनकी खुद की रुचि रही है। करीब 18 साल पहले उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन असफल हो गए थे। अब बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा है और सत्ता सुख मिला है तो अपने पास से क्यों जाने दिया जाए? उनके भीतर तानाशाही के बीज पहले से रहे होंगे जो अब अंकुरित होने के लिए बेताब हैं। सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव टालना ही सबसे बेहतर रास्ता है।

खुद को मजबूत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को अपने साथ लिया। वे यह भी भूल गए कि इसी पाकिस्तान के तानाशाहों और सैनिकों ने बांग्लादेश में नरसंहार किया था और वहां की महिलाओं की अस्मत लूटी थी। पाकिस्तान को साथ लेते ही उन्होंने उस भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया जिसकी बदौलत बांग्लादेश का जन्म हुआ।

उनके सत्ता संभालते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए और वे निर्लज्ज भाव से इनकार करते रहे। इतना ही नहीं वे भारत को धमकाने की कोशिश भी करते रहे। उनके सेना अध्यक्ष वकार-उज-जमां ने यहां तक कह दिया कि अब भारत से आमने-सामने और बराबरी के स्तर पर बात होगी। यह भाषा बताती है कि यूनुस और उनके संगी-साथी चाहते हैं कि भारत किसी तरह नाराज हो।

वे भारत को नाराज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहरबुझी बयानबाजी से जब काम नहीं चला तो उन्होंने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर हरकतें शुरू कर दीं। बीजीबी के नाम से पहचाने जाने वाले बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने सीमावर्ती इलाके में गुंडे मवालियों की सहायता से भारत के भीतर घुस कर रात में भारतीयों की फसलें कटवा दीं। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया।

भारत-बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। अकेले पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा है। सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम वर्षों से चल रहा है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा इलाका खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल से लगे इन्हीं खुले इलाकों में इन दिनों बांग्लादेशी उपद्रव कर रहे हैं।

उनकी चाहत है कि इससे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना आपा खो दे और हालात गंभीर तनाव का रूप ले ले। यदि ऐसा वास्तव में हो जाए तो बांग्लादेश के लोगों को भड़काया जा सकेगा कि भारत समस्या पैदा कर रहा है। एक बार लोग भारत के खिलाफ हो गए तो उस भावना का उपयोग करके चुनाव को टाला जा सकता है।

दरअसल इसी बहाने पाकिस्तान भी बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाना चाहता है। पूर्वोत्तर भारत की सीमा को चीन भी अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को चीन लगातार हथियार पहुंचा रहा है। यदि बांग्लादेश की सीमा पर भी स्थिति खराब होती है तो भारत के लिए एक और गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी।

यूनुस की एक और हरकत पर नजर डालिए तो आपको उनकी धूर्तता का अंदाजा हो जाएगा। हाल ही में उनके एक बेहद करीबी सलाहकार महफूज आलम ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारत के कुछ इलाके बांग्लादेश में शामिल होने चाहिए।

इस तरह की बातों का बस एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह भारत नाराज हो, तूफान पैदा हो और फिर यूनुस बांग्लादेशियों से कह सकें कि देश खतरे में है इसलिए अभी चुनाव की बात मत कीजिए! दुनिया का इतिहास उठा कर देखिए, तानाशाह ऐसी ही चाल चलते हैं। यूनुस में भी तानाशाह बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

आज का इतिहास

1973 संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर का रेट 10ब तक घटा।
1974 असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोलजेनिट्सिन को सोवियत संघ से निकाला गया।।
1976 नाइजीरिया के जनरल मुर्तला मोहम्मद की सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई।
1978 सिडनी में हिल्टन होटल के बाहर एक बम विस्फोट हुआ, जो कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की साइट है, जिसमें तीन लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए।
1981 अमेरिका के लुइसविले, केंटकी में सड़कों के दो मील (3 किमी) से अधिक हेक्सेन वापर्सडेस्ट्रायड के प्रज्वलन के कारण सीवर विस्फोट।
1983 इटली के ट्यूरिन में एक सिनेमा घर में आग लगने से 64 लोगों की मौत हुई।
1991 अमेरिका ने इराक पर बम बरसाये जिसमें 334 लोग मारे गये।
1991 खाड़ी युद्ध: संयुक्त राज्य वायु सेना ने बगदाद, इराक में एक हवाई-छाप आश्रय पर दो लेजर-निर्देशित स्मार्ट बम गिराए, जो माना जाता था कि एक सैन्य कमान स्थल था, जिसमें कम से कम 408 नागरिक मारे गए थे।
1997 हबल टेलीस्कोप को डिस्कवरी द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
1998 हॉवर्ड स्टर्न ने घोषणा की कि वह फिल्म प्राइवेट पार्ट्स बनाते हैं।
2000 यूएस फीमेल फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप और साथ ही यूएस मेल फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2000 में आयोजित की गई थी।
2001 मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 6.6 तीव्रता वाले भूकंप से कम से कम 400 लोगों की मौत हुई।
2008 प्रधान मंत्री, केविन रुड ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों के लिए एक औपचारिक माफी जारी करते हैं।
2008 ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री केविन रुड ने स्वदेशी ऑस्ट्रेलिया और चोरी की पीढ़ी से माफी मांगी।
2010 जॉर्जियन लूगर, नोडर हमारिशश्विली की ओपनिंग सेरेमनी से पहले 2010 वैंकूवर ओलंपिक के लिए एक ट्रेसिंग रन के दौरान एक घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

प्रवेश वर्मा नहीं, ये हो सकते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री

अभिनय आकाश

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले आए हैं। दिल्ली में कमल का कमाल ऐसा दिखा कि इसने झाड़ू के तिनके को बिखेड़ कर रख दिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज सरीखे नेता को भी जनता ने विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस का तो नामोनिशां इस बार भी नहीं दिख रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने इस बार भी इतनी बड़ी जीत कैसे पा ली? दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी करो या मरो के मूड से मैदान में उतरी थी। उसके हाथ से सत्ता गए 27 साल हो गए थे। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार धमाकेदार तरीके से चल रही है। लेकिन दिल्ली में 90 के दशक में सत्ता में आने के बाद से ऐसे बाहर हुई कि ढाई दशक तक अपना सीएम बनाने का ख्वाब हकीकत में नहीं तब्दील हो सका। लेकिन इस बार दिल्ली में बीजेपी ने पूरा दम लगाया। दिल्ली में पिछली दफा आखिरी बार बीजेपी की तरफ से 1998 सुषमा स्वराज ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। अब बीजेपी की तरफ से 27 साल का वनवास खत्म कर मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा भी तेज हो चली है। क्या अमित शाह प्रवेश वर्मा को आगे करेंगे या किसी अन्य नेता की लॉटरी लग सकती है। कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर मोदी-शाह का फैसला क्या होगा?

दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला है। दूसरे विधानसभा सीटों के मुकाबले देश की राजधानी के चुनाव परिणाों को लेकर आम लोगों की दिलचस्पी को नेशनल मीडिया में मिल रही कवरेज से आंका जा सकता है। ये दिलचस्पी दिल्ली के नेशनल कैपिटल होने की वजह से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की वजह से भी है। अरविंद केजरीवाल ने देश में नई तरह की राजनीति की शुरुआत की। सरकारें आम जनता के फायदे के लिए बहुत पहले से काम करती नजर आ रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाली मुफ्त की घोषणाओं ने उन्हें दिल्ली और पंजाब में मशहूर कर दिया। एक तरह से वो हीरो बन गए। लेकिन इस बार बीजेपी की हार से ज्यादा केजीरावल के हार के चर्चे हैं। इसके साथ ही वो जिस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी पर हार्ड हिटिंग करते हैं उससे देश में काफी लोग ये मानने लगे कि मोदी का मुकाबला वही कर सकते हैं।

जिस तरह आम चुनाव के दौरान देश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द घूमती है। कुछ उसी तरह दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के आस पास ही रहता है। चाहे वो जीते या हारे वो चुनाव का चेहरा हैं। बाकी सभी उनकी प्रतिक्रिया में अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस बार दिल्ली की राजनीति से देश की राजनीति पर प्रभाव साफ नजर आने वाला है। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ उसका सूखा खत्म हो गया। पूरे चुनाव दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी को इसे मुद्दे पर घेरती रही है कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिन दूल्हे की बारात भी निकाल चुकी है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती झेली। बीजेपी की जीत के साथ ही अब पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के नामों पर दबे जुबान में चर्चा शुरू हो चुकी है।

बीजेपी में यूं तो विधायक दल ही अपना नेता चुनता है। लेकिन आज की तारीख में माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हामी बहुत मायने रखती है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों के बाद माहौल में आरएसएस की सहमति की भी अपेक्षा की जा सकती है। दिल्ली बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर तीन से चार नामों की जानकारी

सामने आ रही है। बीजेपी के सीएम दावेदारों में सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आ रहा है। उसके बाद आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। तीसरे नाम के तौर पर निर्वतमान विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुनाई पड़ रहा है।

दिल्ली के रजौरी गार्डन से विधानसभा चुनाव में उतरने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े सिख चेहरे हैं। रजौरी गार्डन में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से धनवती चंदेला और कांग्रेस के धर्मपाल चंदेला से हुई। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के धनवती चंदेला ने 62,212 वोट पाकर जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रमेश खन्ना रहे थे। 2013 में सिरसा इसी सीट से शिरोमणि अकाली दल से चुनाव जीते थे। तब शिअद एनडीए का हिस्सा थी। इस सीट पर 2017 में उपचुनाव हुए थे। दरअसल, इस सीट से आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा देने की वजह से उप चुनाव हुए थे। सिंह ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से अपनी सदस्यता छोड़ी थी। उपचुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से ये सीट छीन ली थी। उसके उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने 40,602 वोट पाकर जीत हासिल की थी। 2021 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक साथ दिल्ली से लेकर पंजाब को भी साधना चाहती है। किसान आंदोलन की वजह से सियासी तौर पर ऐसी धारणा बनी है या बनाई गई है कि बीजेपी से सिख समुदाय का एक बड़ा तबका नाराज है। दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों की भी अच्छी जनसंख्या है। वे आबादी के 4.43 प्रतिशत हैं।

दिल्ली के बिजवासन सीट से मैदान में उतरे कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। दिल्ली में 15 अगस्त 2024 को एलजी ने उन्हें ही झंडा फहराने का मौका दिया था। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनका मुकाबला पिछली बार आप के सुरेंद्र भारद्वाज और कांग्रेस ने देविंदर सेहरावत से हुआ। आप की ओर से कैलाश गहलोत दिल्ली की नजफगढ़ सीट से लगातार दो बार (2015 और 2020) चुनाव जीते थे, जबकि इस बार भाजपा ने उन्हें बिजवासन से अपना उम्मीदवार बनाया। कैलाश गहलोत जाट बिरादरी से आते हैं। जिसका दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा दबदबा है। बीजेपी अगर इन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो इसके जरिए एक तो जाटों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने उसी के पुराने नेता को खड़ा करके उसके जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। चुनाव से पहले केजरीवाल ने जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग करके इस वर्ग को खुश करने का दांव चला था। लेकिन वो सफल नहीं हो सके।

रोहिणी से चुनाव मैदान में उतरने वाले विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के मौजूदा विधायक भी रहे हैं। गुप्ता रोहिणी से ही पहले भी लगातार दो बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला आप के निगम पार्षद प्रदीप मित्तल और कांग्रेस के सुमेश गुप्ता से हुआ। इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद को बनिया बताते हुए वैश्य समाज का वोट पाने की कोशिश करते देखे गए। गुप्ता दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वो बीजेपी के दिल्ली के बड़े चेहरे माने जाते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार केजरीवाल और आप के खिलाफ पार्टी के धाकड़ नेता की भूमिका निभा रहे हैं। इनका पार्टी कैडर भी काफी मजबूत है और उस पर पकड़ भी है। संगठन में गुप्ता की स्थिति मजबूत मानी जाती है।

हालांकि प्रवेश वर्मा के बारे में इस बात की चर्चा है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा देने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत कर ली है। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद उनके गृह मंत्री अमित शाह संग मुलाकात की भी खबर सामने आई है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा जाट चेहरा भी हैं। ये वो नाम है जिनकी चर्चा तेज है। लेकिन बीजेपी हर बार सीएम के नामों को लेकर चौंकाती रही है। ऐसे में क्या इस बार भी दिल्ली में ऐसा ही हो सकता है। सीएम फेस को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में बीजेपी ने हमेशा चौंकाया है। यानी बीजेपी की रणनीति मुख्यमंत्रियों को लेकर ऐसी रही है जिससे राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान रह गए।

पंजाब बचाने की चुनौती से कैसे निपटेंगे केजरीवाल?

अमित शर्मा

दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद %दिल्ली मॉडल% पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मॉडल केजरीवाल की दिल्ली की सत्ता बचाने में नाकाम साबित हुआ है, ऐसे में अब इस मॉडल के सहारे पार्टी दूसरे राज्यों में वोट भी नहीं मांग सकेगी। अब पार्टी को एक दूसरे जिताऊ मॉडल की जरूरत है। केजरीवाल की यह जरूरत पंजाब में पूरी हो सकती है जहां फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पंजाब की सरकार बचाने की है। पंजाब के विधायकों के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार को वही मंत्र दिया है जिसके सहारे पार्टी की लोकप्रियता को न केवल बढ़ाया जा सके, बल्कि अगले चुनावों में सरकार की वापसी की राह भी तैयार की जा सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों-मंत्रियों को जनता की सेवा में पूरी ताकत के साथ जुटने का मंत्र दिया है। इसके साथ ही उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है जिसे करके पार्टी पंजाब में सत्ता में आई थी। इसका सीधा अर्थ यह है कि पंजाब सरकार अब जल्द ही महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने की योजना पर मुहर लगा सकती है। इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए दूसरे राज्यों में इसी तरह की योजनाओं को देखते हुए इस सम्मान राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा दलित छात्रों के लिए विशेष योजनाओं, महिलाओं और युवाओं को जल्द से जल्द बेहतर योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जा सकती है। दरअसल, दिल्ली की हार के बाद कांग्रेस और भाजपा पंजाब को लेकर हमलावर हो गए हैं। पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर भगवंत मान पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि यदि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में असफल रहती है तो आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस-भाजपा इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि अब जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजीव कौशिक ने कहा कि पंजाब में बदलाव की बात बेबुनियाद है। यह अफवाह उड़ाकर कांग्रेस पंजाब में बढ़त हासिल करना चाहती है, लेकिन उनके सभी विधायक-मंत्री उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं-बच्चों के लिए बेहतर सुविधा देना ही आम आदमी पार्टी की राजनीति का मूल मंत्र रहा है, आज की बैठक में भी अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को सेवा करके जनता के करीब जाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बारे में अफवाह फैलाकर कांग्रेस और भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है। वे लगातार दूसरी बार भी सत्ता में आने में कामयाब रहेंगे।

कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों में भी पतन का दौर

अजय कुमार

देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उभार और कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दलों का पतन काफी कुछ कहता है। भले ही हार से बौखलाए मोदी और बीजेपी विरोधी नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हों ? सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करते हों ? लेकिन ऐसा नहीं है कि विरोधियों को अपनी राजनैतिक कमजोरी और सियासी अपरिपक्वता का अहसास नहीं है,लेकिन बार-बार पराजित हो रहे यह नेता सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बीजेपी को छोड़कर देश की किसी भी राजनैतिक दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है। इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी,समाजवादी पार्टी,राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल,उद्धव ठाकरे की शिवसेना,शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की लम्बी चौड़ी लिस्ट हैं। अब इसमें नया नाम कट्टर ईमानरदार 'आम आदमी पार्टी' का भी जुड़ गया है।

हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हार के लिये अभी तक ईवीएम मशीन या सरकारी मशीनरी पर किसी तरह की धांधली का आरोप नहीं लगाया है,जबकि

उसी समय उत्तर प्रदेश में अयोध्या की चर्चित मिल्कीपुर विधान सभा सीट पर मिली जबर्दस्त हार के बाद समाजवादी पार्टी का प्रलाप लगातार जारी है। ऐसा ही प्रलाप कांग्रेस अध्यक्ष खरगे,नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सहित उनकी पार्टी के तमाम नेता भी करते रहते हैं। हालात यह है कि हार से बौखला कर मोदी विरोधी नेता उन्हें(मोदी) और बीजेपी को ही नहीं चुनाव आयोग,सीबीआई,ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ भी भड़ास निकालते रहते हैं। यह नेता मोदी को नीचा दिखाने के लिये देश की छवि भी खराब करने से नहीं चूकते हैं। इसमें विदेश से पढ़ाई करके आने वाले टेक्नोटेक सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आईआरएस रह चुके अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता शामिल हैं तो बिहार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी आरोप-प्रत्यारोप वाली सियासत से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी आभा को एकदम मटियामेट कर दिया है. जो केजरीवाल 12 साल पहले यूथ आइकॉन बनकर उभरे थे, वे अब धूल में लथपथ पड़े हैं. विधान सभा में 'दिल्ली का मालिक मैं हूँ' जैसे अहंकारी बयान देने वाले और हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर अपनी फजीहत करा चुके अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे आधे-अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे थे मगर अब वे विधायकी भी गंवा बैठे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कि अरविंद जिस तेजी से राजनीति में चमके थे उसी तत्परता से औंधे मुंह जा गिरे। अब उनका कोई भविष्य नहीं है और इसकी वजह है उनका बड़बोलापन और भरोसे की राजनीति न करना एवं उनकी अवसरवादिता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से अधिक भद्द राहुल गांधी की पिटी है। पिछले कई चुनावों से दिल्ली में शून्य सीटों का रिकॉर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम दर्ज है।

अरविंद केजरीवाल की तरह ही नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनैतिक विरासत संभाले हुए अखिलेश यादव की है। 2012 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था,जबकि अनुभव के नाम पर अखिलेश खाली हाथ थे। इसके बाद अखिलेश यादव अपने दम पर भले ही राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाये हों,लेकिन उनके बड़बोलेपन और अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की महारथ के चलते खूब नाम कमा रहे हैं।विवादित बयानबाजी की बात की जाये तो अखिलेश यादव अपने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का नया राजा कहकर प्रभु श्रीराम और उनके भक्तों का उपहास उड़ाने के चक्कर में खुद फजीहत करा बैठते हैं। उन्हें ट्रॉफी की तरह अपने साथ लेकर घूमते थे,लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश अपने होश खो बैठे हैं। सपा नेता हार से इतना बौखला गये हैं कि पार्टी के महासचिव प्रो रामगोपाल यादव तो यूपी के सरकारी अधिकारियों को ही नसीहत देने लगे हैं कि वह मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश सुनने की बजाये उन्हें नसीहत दें। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव हताशा में डूबते जा रहे हैं। रामगोपाल तो अयोध्या में रामलला के मंदिर को भी बेकार कह चुके हैं। सपा के तमाम नेता महाकुंभ में कथित अव्यवस्था को लेकर भी लगातार सीएम पर हमलावर हैं,लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को हासिल क्या हो रहा है,यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।क्योंकि समाजवादी पार्टी का पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मिल्कीपुर में तो सपा को यादवों तक का वोट नहीं मिला।

'कांग्रेस मुक्त भारत' धरातल पर दिखने लगा

श्वेत मलिक

चुनावी सफलताओं के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा के लिए मजबूत जन समर्थन से पिछला समय काफी शानदार रहा। वहीं परिवारवादी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस कमजोर नेतृत्व व वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपने जातिवाद व धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण देश में अपने न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है व 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा धरातल पर दिख रहा है। भारतीय राजनीति की 'वयोवृद्ध पार्टी' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा/एन.डी.ए. के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। पांच साल बाद 2019 में मोदी ने अपने नेतृत्व में भाजपा/एन.डी.ए. को उससे भी बड़ी जीत दिलाई व 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है।

'इंडिया टुडे' के सर्वे में 57.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कांग्रेस अपने अंत की ओर बढ़ रही है। एक अन्य सर्वे में 71.4 प्रतिशत ने कहा कि भारतीय मतदाताओं ने निर्णायक रूप से वंशवादी कांग्रेस की राजनीति को खारिज कर दिया है। ऐसे ही कराए गए एक अन्य सर्वे में 68.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से गुजर रही है व अपने अंत के करीब है। लेकिन अब तक भी 140 साल पुरानी पार्टी के पुनर्जीवित होने के संकेत नहीं दिखते।

7 अगस्त, 2020 को कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाई वपार्टी के अध्यक्ष पद समेत विभिन्न संगठनों के चुनाव कराए जाने की मांग के साथ ही नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। श्रीमती सोनिया

गांधी ने डमी मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष तो बनाया, पर संगठन की चाबी अपने पास रखी व अब अपने गांधी परिवार को 3 सांसदों का तोहफा देकर फिर कार्यकर्त्ताओं की अनदेखी की।

लगातार चुनावों में हार मिलने के बाद भी पार्टी में नेतृत्व के संकट को दूर करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठता नहीं दिखा। 'बागियों' और 'परिवार के तथाकथित वफादारों' के बीच की दरार कांग्रेस पार्टी को लगातार डरा रही है। कांग्रेस पार्टी की आजादी के बाद इतनी बड़ी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। पतन के कारण तो बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बात करूंगा-

1. कांग्रेस पार्टी का मुखिया बस गांधी ही हो, भले ही उसको भारत की जमीनी हकीकत पता न हो, पतन के कारण में पहले स्थान पर है।

2. राहुल गांधी पतन के दूसरे नम्बर पर फिट बैठते हैं। इनको राजनीति का 'र' भी नहीं पता, बस गांधी होने का टैग है। वह सीधे पी.एम. की कुर्सी के हकदार, बाकी कर्मठ नेताओं का अनुभव गांधी टैग के सामने कुछ भी नहीं।

3. मुस्लिम तुष्टीकरण = डूक्षहदू बहुल भारत में डूक्षहदुओं को उनके ही देश में दूसरे स्थान पर रखना।

4. इटली में जन्मी श्रीमती सोनिया गांधी, वह सिंहासन पर बैठ कर जनता से सीधे संवाद नहीं करना चाहतीं क्योंकि उनको डूक्षहदी नहीं आती, देश की सम्माननीय राष्ट्रपति को गरीब महिला संबोधित कर देश का अपमान करती हैं।

5. चाटुकार नेताओं को पार्टी में जगह देना, जो जमीन पर नहीं जाना चाहते, बस कांग्रेस में ऊंचे पद पर बैठ कर गांधी परिवार की चापलूसी करते हैं।

6. कांग्रेस के 70 साल के शासन में देश के पैसों को विदेशों में भेजना, जिसे काला धन कहते हैं।

7. कांग्रेसियों को पाकिस्तान से आए हिन्दू से कोई मतलब नहीं, पर रोहिंग्या, बंगलादेशीयों से इतनी हमदर्दी जनता की आंखों में सीधे गढ़ती है।

8. इनकी ऐसी क्या मजबूरी है, जो ये देशद्रोह कानून को खत्म करना चाहते हैं।

9. भाजपा जैसे राष्ट्रभक्त संगठन व कार्यकर्त्ताओं का न होना पतन का बहुत बड़ा कारण।

10. देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर देश के साथ धोखा करना, आज मोदी जी सरकार में आधुनिक हथियार हैं, व देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा. जो कांग्रेस राज में नहीं था।

11. कश्मीर जैसे मुद्दे को सुलझाने में कोई भी योगदान नहीं देना।

12. देश में कांग्रेस शासन में बड़े-बड़े आतंकवादी हमले, जिनपर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल होना।

13. देश की जनता को जातियों में बांट कर राज करो का षड्यंत्र किया।

14. देश के हिन्दू मंदिरों का ध्यान न कर सरकारी धन मस्जिदों को बांट हिंदुओं से अन्याय किया व वोट बैंक के लिए वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का समर्थन।

15. सेना के चीफ को गाली व गुंडा कहा। देश के पी.एम., विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को निरंतर गाली देना।

16. राहुल गांधी, सोनिया गांधी द्वारा बड़े-बड़े घोटाले करना, जो कोर्ट से जमानत पर रिहा हैं।

17. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से देश को कठपुतली की तरह चलवाना।

18. सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना, सेना से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना।

19. भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह जैसे विवाद में राहुल गांधी का सीधे जे.एन.यू. में जाकर देश के गद्दारों का समर्थन करना।

20. चीन के साथ डोकलाम विवाद के वक्त चुपके से चीन के राजदूत से राहुल गांधी का मिलना।

21. आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल की खरीद पर राहुल गांधी का झूठ, बाद में उच्चतम न्यालय में माफी मांगी।

22. स्वामीनाथन आयोग द्वारा फसल की न्यूनतम मूल्य वृद्धि करने की सिफारिश को किसान विरोधी कांग्रेस ने 9 वर्ष लागू नहीं किया।

23. 1984 में दिल्ली सिख नरसंहार में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता होना।

24. देश को धर्म के आधार पर बांटने के लिए कांग्रेस शासन में हर दिन हिंदू-मुस्लिम दंगे होना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'कांग्रेस मुक्त भारत' का उनका नारा राजनीतिक रूप से मुख्य विपक्षी दल को समाप्त करने का नहीं, बल्कि देश को कांग्रेस संस्कृति से छुटकारा दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस खुद भी कांग्रेस संस्कृति से मुक्त हो, यह देश के हित में होगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है।

चुनावी हार से बड़ी है एक सपने की मौत

योगेन्द्र यादव

सवाल यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी (आप) का क्या होगा या कि अब केजरीवाल कहां जाएंगे? सवाल है कि वैकल्पिक राजनीति की किसी भी कोशिश का क्या भविष्य है? यह सवाल उन लोगों को भी पूछना चाहिए, जिन्हें 'आप' से कभी मोह नहीं रहा था या जिनका मोहभंग हो चुका है। जहां तक आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का संबंध है, उसमें अभी कुछ वक्त अनिश्चितता बनी रहेगी। वैसे तो तीन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद एक चुनाव में पिछड़ जाना और वह भी सिर्फ 4 प्रतिशत मतों से, यह कोई ऐसी हार नहीं है जिसके बाद किसी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाएं। लेकिन यह सादा तर्क 'आप' पर लागू नहीं होता। एक आन्दोलन से शुरुआत करने वाली यह पार्टी पूरी तरह से चुनावी पार्टी बन गई और जल्द ही संगठन को छोड़ सरकार तक सीमित हो गई। इसलिए चुनावी हार का धक्का ज्यादा भारी पड़ सकता है। शुरू से ही पार्टी की दिल्ली पर निर्भरता बहुत ज्यादा रही है, पंजाब सरकार भी दिल्ली दरबार से चलाने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए दिल्ली की हार का असर पूरे देश पर पडना स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल को पार्टी का चेहरा ही नहीं, पार्टी का पर्याय बनाने का खमियाजा यह है कि उनकी व्यक्तिगत चुनावी हार का वही असर हो, जो युद्ध में सेनापति के गिरने का होता है। दिल्ली के बाहर 'आप' के लिए बहुत रास्ते खुले नहीं हैं। पिछले चुनाव में गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में अच्छे वोट मिले थे, लेकिन आगामी चुनाव में उसे दोहराना संभव नहीं लगता। हरियाणा में घुसने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अन्य किसी नई जगह गुंजाइश नहीं दिखती। ले देकर अब सारा दारोमदार पंजाब पर टिका है। वहां सत्ता बचाए रखना एक टेढ़ी खीर हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में पंजाब के विधायकों में बगावत की चर्चा को खारिज भी कर दिया जाए तो भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 'आप' के सामने अनेक चुनौतियां हैं। खजाने में पैसे नहीं हैं, सरकार का इकबाल नहीं है, मुख्यमंत्री में समझ नहीं है, पार्टी को दिशाबोध नहीं है। पंजाब के मतदाता में बहुत धीरज नहीं है और अगर पंजाब की सरकार भी चली जाती है तो पार्टी के अस्तित्व का संकट हो सकता है। यह संकट इसलिए गंभीर हो सकता है, क्योंकि 'आप' ने उन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं से किनारा कर लिया है, जिनकी निस्स्वार्थ मेहनत के दम पर पार्टी खड़ी हुई थी। धीरे-धीरे सब जगह या तो दूसरी पार्टियों से नेताओं को भर लिया गया है, या फिर वे कार्यकर्त्ता हैं, जिनकी नजर कुर्सी पर लगी है। ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन या फिर सी.बी.आई. या ई.डी. को हथियार बनाकर 'आप' को तोडने की कोशिश होती है तो कितने ऐसे नेता इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होंगे? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई यह पार्टी राजनीति के स्थापित ढर्रे को बदलने के उद्देश्य से बनी थी, लेकिन पहले 3 साल के भीतर ही राजनीति को बदलने की बजाय इस पार्टी ने राजनीति के स्थापित कायदे के हिसाब से खुद को बदल लिया। दरअसल दिल्ली में 2015 के चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता इस पार्टी की बुनियादी विफलता से जुड़ी थी। जल्द से जल्द चुनावी सफलता के लिए पार्टी ने अपने बुनियादी मूल्यों और सिद्धांत को ताक पर रख दिया था। इससे सरकार तो बन गई, मगर पार्टी टूट गई। पार्टी के लोकपाल से लेकर पार्टी की सर्वोच्च समिति और जमीनी कार्यकर्त्ता तक वे सब लोग पार्टी से अलग कर दिए गए, जो कुछ आदर्श को लेकर पार्टी से जुड़े थे। पार्टी में हर स्तर पर अवसरवादी नेताओं को भर लिया गया। दिल्ली में घटी इस कहानी को अलग-अलग समय पर सभी राज्यों में दोहराया गया। वैकल्पिक राजनीति का सपना तो उस वक्त ही मर गया था। लेकिन एक राजनीतिक विकल्प के रूप में 'आप' बनी रही और मजबूत भी हुई। भ्रष्टाचार विरोधी आदर्शवाद को छोड़कर अब पार्टी ने 'गुड गवर्नेंस' का नारा पकड़ा। दिल्ली सरकार की बड़ी तिजोरी के सहारे मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं भी पेश कीं। सरकारी स्कूलों में सुधार और मोहल्ला क्लिनिक के सहारे 'दिल्ली मॉडल' की पेशकश की। हालांकि 'शिक्षा क्रांति' जैसे दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे, फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दिन बाद सरकारी स्कूलों की सूरत सुधरी।

फिजियोथैरेपी वक्त की मांग

कॅरियर गाइडेंस देश व दुनिया में आज हेल्थ सेक्टर का जितना विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे चलकर काबिल फिजियोथैरेपी की मांग और बढ़ेगी। फिजियोथैरेपी विज्ञान की ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम के जरिए व्यक्ति के रोगों व व्याधियों का उपचार किया जाता है।

फिजियोथैरेपिस्ट का काम रोगियों में किसी बीमारी, चोट, अक्षमता या बढ़ती उम्र की वजह से उपजी शारीरिक व्याधियों का उपचार करना है। आज लोग बीमारी के उपचार के लिए समग्र नजरिया अपनाने लगे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में फिजियोथैरेपिस्ट्स की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है।

काम का दायरा

फिजियोथैरेपिस्ट्स अस्पतालों, विकलांगों की लिए बने पुनर्वास केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए बने स्कूलों, स्वास्थ्य संगठनों के अलावा डिफेंस मेडिकल प्रतिष्ठानों और स्पोर्ट्स क्लबों में भी अपनी सेवाएं देते है। इंजुरी व फैक्चर्स, जोड़ों के दर्द, खिंचाव, मोच, स्ट्रोक्स के उपचार में काबिल फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं कारगर साबित होती हैं।

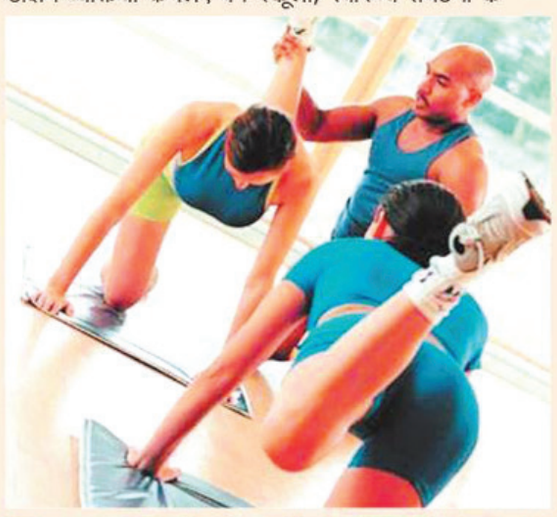

बढ़ती मांग

आज जिस तरह के अत्याधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र व क्लीनिक्स खुल रहे हैं और हेल्थ सेक्टर का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फिजियोथैरेपिस्ट की मांग आगे चलकर और बढ़ेगा। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खुद को फिट रखने व फिटनेस संबंधी सुझाव लेने के लिए फुलटाइम पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की सेवाएं लेते हैं। विदेशों में और खासकर अमेरिका कनाडा व आस्टेलिया जैसे देशों में पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की जबदस्त मांग है।

योग्यता

फिजियोथैरेपी में कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए। अस्पताल व क्लीनिक्स अमूमन ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं, जिनके पास फिजियोथैरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी) हो। बीपीटी करने के बाद छात्र यदि चाहें तो अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं।
फिजियोथैरेपी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि छह महीने से लेकर दो साल तक हो सकती है। डिग्री स्तर अवधि तीन से चार साल तक होती है। प्रतिष्ठित संस्थान कॉमन टेस्ट सीईटी के जरिए बीपीटी में छात्रों की दाखिला देते है।

व्यक्तिगत योग्यता

फिजियोथैरेपिस्ट्स बनने के चाह रखने वाले अभ्यर्थियों में लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। काबिल फिजियोथैरेपिस्ट वहीं है जो मरीज की जरूरत को अच्छी तरह समझ सके, उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। सफल फिजियोथैरेपिस्ट बनने के लिए व्यक्ति में इन खूबियों के अलावा मानवीय संरचना का सम्पूर्ण ज्ञान होना भी अति आवश्यक है।

पारिश्रमिक

इस क्षेत्र से जुड़े कोई फ्रेश ग्रेजुएट किसी हॉस्पिटल या क्लीनिक में टेनी फिजियोथैरपिस्ट के तौर पर 8,000 से 12,000 रूपए वेतन पाने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्रतिष्ठित अस्पतालों में आपको और भी अच्छा वेतन मिल सकता है। अनुभव हासिल करने के बाद आपके वेतन में खासा इजाफा हो सकता है। अनुभवी फिजियोथैरपिस्ट चाहे तो निजी क्लीनिक खोल कमाई कर सकते हैं।

डायटीशियन

कॅरियर का बेहतर विकल्प

आहार जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो आहार लेते है उसका शरीर में पाचन किया जाता है। प्रकृति ने विभिन्न खाद्य-पदार्थों को भोजन का रूप दिया है जिसे कच्चा या पका कर हम उपयोग करते हैं ऐसे पदार्थ हमारे पाचक अंगों द्वारा पचा लिए जाते हैं, जिनसे ऊतकों का निर्माण एवं पोषण होता है। चलने, फिरने दौडने या अन्य शारीरिक कार्य करते रहने से शरीर के भीतर के ऊतक टूटते-फूटते एवं घिसते रहते है। भोजन द्वारा हमारे शरीर की संरचना तथा मरम्मत के लिए विभिन्न पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिनसे हमें शक्ति मिलती हैऔर हमारे शीरीरिक के विभिन्न अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं सन्तुलित आहार और सही आहार हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है लिहाजा हमारी शारीरिक जरूरतों के अनुसार कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती हैं और कौन से खाद्य-पदार्थ से सेहत को नुकसान पंहुच सकते है, इसका जवाब डायटीशियन ही बता सकता है। जीवनशैली में आ रहे बदलावों और उसके दुष्णपरिणाम के चलते डायटीशियन एक बेहतर केरियर ऑप्शन के रूप में उभरा है। यह कोर्स अपनाकर आप अपना ही नहीं दूसरो की सेहत का भी ख्याल रख सकते है। एक डायटीशियन के रूप में आप नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग, बीमार, अभिनेताओं और खिलाडियों तक की डाइट का चार्ट बना सकते हैं। डायटीशियन लोगों को सलाह देता है, कि उसे स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए। डायटीशियन का कार्य जितना आसान दिखाई देता है वास्तव में वह उतना आसान नहीं हैं, क्योंकि रोगियों के लिए व्यक्तिगत आहार योजना बनाते हुए विभिन्न क्लीनिकल घटकों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही रोगियों की जीवनशैली, खान-पान की आदतों पर भी विचार करना होता है ापोरेट स्तर पर डायटीशियन की मांग बढ रही है और पांच सितारा होटलों में भी डायटीशियनों की सेवाएं ली जा रहीं हैं।

कराटे- दुश्मन को बिना किसी हथियार से हराने की तकनीक

कराटे निहत्थे लडने की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है। जिस व्यक्ति को कराटे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक कराटे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं कराटे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। कराटे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है।

कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। कराटे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं। इन सभी भागों को कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से कठोर बनाया जाता है। एक कराटे एक्सपर्ट कई इंच मोटी लकड़ी को अपने हाथ या पैर से तोड़ सकता है। सही टाइमिंग, कुशलता तथा जज्बा तो इसके लिए जरूरी है ही साथ ही जरूरी होती है शारीरिक कठोरता।

कराटे के खेल में वार को शरीर के संपर्क में आने से एक इंच पहले ही रोक लिया जाता है। कराटे में मैच सिर्फ 3 मिनट के होते हैं। एक खेल के तौर पर इसमें कुशलता का स्तर परखने के लिए दोनों में नकली लड़ाई और औपचारिक परीक्षण दोनों का आयोजन किया जाता है। यदि प्रतियोगी अच्छे से वार न कर पाए तो जज अपना फैसला मूवमैंट्स और डिफेंस तकनीक के आधार पर सुना सकते हैं ।जजों द्वारा खिलाडियों के प्रदर्शन को वैसे ही रेटिंग दी जाती है, जैसे जिम्नास्टिक में होता है। कराटे एशिया में विकसित हुआ जिसे कई शताब्दियां लग गईं और 17वीं शताब्दी के दशक में जाकर यह कला के रूप में व्यवस्थित होने लगा। 1920 के दशक में यह जापान में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज पूरे विश्व में कई स्कूल कराटे की ट्रेनिंग देते हैं। 1970 में कराटे वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल की स्थापना की गई थी।

प्राचीन चीन से शुरू और जापान में प्रसिद्ध हुआ युद्ध कौशल (मार्शल आर्ट) कराटे आज पूरे विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय है। कराटे खेल भी, कला भी कराटे निहत्थे लडने की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है।

जिस व्यक्ति को कराटे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक कराटे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं कराटे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। कराटे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। कराटे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं।

स्वरोजगार

कागज़ उद्योग

देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से कागज़ उद्योग देश का सबसे पुराना और अति महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग का अनुमानित आकार 25000 करोड़ रुपये (5.95 बिलियन डॉलर) है। विश्व के कागज और कागज बोर्ड उत्पाद में इसका हिस्सा लगभग 1.6 प्रतिशत है। इस उद्योग से 1.20 लाख लागों को प्रत्यक्ष रूप से और 3.40 लाख लोगों को परेक्ष रूप से रोजगार मिला हे। अधिकतर पेपर मिल पिछले लम्बे अर्से से कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार वर्तमान समय में इनमें पुरानी से लेकर अति आधुनिक तकनीक वाली दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ इस्तेमाल हो रही हैं।

पिछले पाँच वर्षों से कागज़ की खपत लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। कागज़ उद्योग को कागज के उत्पादन की किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है; जैसे क्रीमवोव, मैपलिथो, कोपलर, कोटेड पेपर, इंडिस्ट्रयल पेपर और स्पेस्लिटी पेपर। इंडिस्ट्रयल पेपर अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है, जो कि कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत है। अभी तक कागज उद्योग की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के बराबर रही है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें औसतन 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर भारत में कागज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है ओर यह उत्सावर्धक स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक संवृद्धि के साथ कागज की खपत में भी अत्याधिक उछाल आने की संभावनाएँ हैं और यह 2015-16 तक 13.95 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। भावी अनुमान यह हे कि कागज की खपत में सकल घरेलू उत्पाद के गुणांकों में वृद्धि होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति 1 किलाग्राम खपत की वृद्धि से उसकी मांग में 1 मिलियन टन की वृद्धि होगी। उद्योग के अनुमानानुसार वर्ष 2012-13 तक कागज़ उत्पादन 8.4 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ा है, जबकि कागज की खपत 9 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ी है। कम खर्च व लागत में कागज उद्योग स्वरोजगार का बेहतर जरिया बन सकता है।

पैरा-मैडीकल कोर्सेज में संवारें कॅरिअर

यदि आपकी बारहवीं परीक्षा की श्रेणी या अंक बहुत अच्छे नहीं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि पैरा-मैडीकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए सी.पी.एम.टी. जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती। डॉक्टर जब मरीज को देख लेता है उसके बाद (कुछ मामलों में डाक्टर से पहले भी) सारा काम पैरा-मैडीकल के लोग ही संभालते हैं।

मरीज के खून, पेशाब, बलगम, वीर्य, टिश्यू आदि की जांच करनी हो, उसका एक्स-रे, ई.सी.जी., ई.ई.जी., एम.आर.आई., अल्ट्रा साऊंड, सी.टी. स्कैन, टी.एम.टी.,पी.एफ.टी., मैमोग्राफी आदि इंजैक्शन व दवा देनी हो तथा इसके अलावा भी अनेक ऐसे काम हैं जिसे पैरा-मैडीकल स्टाफ ही करता है। आप्रेशन करते समय एक डाक्टर को असिस्ट करने के लिए पैरा-मैडीकल स्टाफ होता है। मैडीकल फील्ड का लगभग सारा टैक्निकल स्टाफ पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही आता है।

इसके तहत प्रमुख कोर्स व संबंधित कार्य इस प्रकार हैं- मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी , एक्स-रे टैक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी/रेडियोग्राफी, ऑप्टोमीट्री या ऑप्थाल्मिक टैक्नोलॉजी, प्रॉस्थैटिक एवं ऑथोटिक इंजीनियरिंग, फिजियोथैरिपी एंड ऑकुपेशनल थैरेपी, डैंटिस्ट असिस्टैंट, स्पीच थैरेपी एंड ऑडियोलॉजी, क्लीनिकल चाइल्ड डिवैल्पमैंट, रिहैबिलिटेशन, मैडीकल ट्रांसक्रिप्शन, कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स कोर्स (मेल/फीमेल/मल्टीपर्पज़) ऑप्रेशनल थैरेपिस्ट असिस्टैंट/ ऑप्रेशन थिएटर असिस्टैंट व टैक्नीशियन कोर्स, कॉर्डियोलॉजी टैक्नीशियन कोर्स, सी.टी. स्कैन टैक्नीशियन कोर्स।

इनके साथ ही फॉर्मेसी, नर्सिंग एवं मिडवाइफरी तथा साइकोलॉजी की गणना भी पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही की जाती है। उपरोक्त सभी कोर्सों में सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, बी.एससी., एम.एससी., बैचलर या मास्टर डिग्री विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रदान की जाती है।

संस्थान

- पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सैक्टर-11,चंडीगढ़-1600012
- पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज, रोहतक-124001, हरियाणा।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110007

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी के विमान को आतंकी खतरा

नईदिल्ली। मुंबई पुलिस को एक कॉल मिली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उनके विमान पर आतंकवादी हमले की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को आए धमकी भरे कॉल में दावा किया गया है कि आतंकी पीएम के विमान पर हमला कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, धमकी का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया और उनके जाने से पहले स्थिति का आकलन करने के लिए एक जांच शुरू की गई। मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई जिसमें चेतावनी दी गई कि आतंकवादी पीएम मोदी के विमान पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वह विदेश की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। सूचना की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच शुरू की। मुंबई पुलिस के अनुसार, पुलिस ने धमकी भरे कॉल के पीछे वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने छोड़ा टीएमसी का साथ

कोलकाता। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, जो 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे, बुधवार को कांग्रेस पार्टी में लौट आए। कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से वापसी के बाद अभिजीत ने दूसरी पार्टी में शामिल होने को गलती बताया। गौरतलब है कि पिछले साल जून में अभिजीत ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा था, टीएमसी की कार्य संस्कृति कांग्रेस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। इससे पहले आज, कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने मीडिया को बताया कि वह (अभिजीत मुखर्जी) पिछले साल से नेतृत्व और राज्य पीसीसी के संपर्क में थे। आज, यह निर्णय लिया गया है कि अभिजीत मुखर्जी (प्रणब मुखर्जी के बेटे) फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। टीएमसी द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ अन्य दल भी थे जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था जहां हाल ही में चुनाव हुए थे।

संजय राउत के आरोपों पर अन्ना हजारे का पलटवार

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर 2014 के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों के तहत अनियमितताओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया है। हजारे ने सेना (यूबीटी) नेता की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग चीजों को अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार समझते हैं। आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए हजारे ने कहा, एक विशेष रंग का चश्मा पहनने वाला व्यक्ति दुनिया को उसी के अनुसार देखता है। हाल के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप को हार का सामना करने के बाद, हजारे ने दावा किया कि केजरीवाल ने केवल शराब पर ध्यान केंद्रित किया और लोगों की सेवा करना भूल गए। हजारे मे कहा कि शराब नीति के मुद्दे के साथ पैसा आया और वे उसमें डूब गए। आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई।

मुख्यमंत्री को लेकर फैसले में देरी पर आप का तंज

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कब करेगी? जैसे-जैसे नए सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि संसद का बजट सत्र खत्म होने और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली की राजनीति में कोई विकास हो सकता है। हालांकि, सीएम के फैसले में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी अब भाजपा पर तंज कस रही है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ये बीजेपी में गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 के समूह में गुट एक साथ आ रहे हैं क्योंकि वे (बीजेपी) यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। कक्कड़ ने कहा कि वे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में दिल्ली के लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए? दिल्ली के सीएम चेहरे पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगले दो दिनों में सभी विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। प्रधानमंत्री (अमेरिका दौरे से) वापस आने पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सीएम चेहरे पर चर्चा करेगा।

उद्धव ने शिंदे को सम्मानित करने पर पवार से नाराजगी व्यक्त की

मुंबई। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर बढ़ती दरार के बीच, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के लिए शरद पवार से नाराजगी जताई है। उद्धव सेना के सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी-एससीपी प्रमुख द्वारा शिंदे को दिए गए महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पर नाराजगी जताई है। ठाकरे ने कहा है कि पवार को उपमुख्यमंत्री को सम्मानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि पवार को ठाकरे परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यह पुरस्कार किसने दिया? राजनीतिक नेताओं को दिए जाने वाले ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। हालिया घटनाक्रम में, उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अकेले उतरने की घोषणा की।

आप से उठ गया जनता का विश्वास : गहलोत

जयपुर। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी से जनता का विश्वास उठ चुका है और कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़कर भविष्य के लिए अपनी भूमिका तैयार कर ली है। एक्स पर एक पोस्ट में, गहलोत ने आम आदमी पार्टी के उन दावों का भी खंडन किया कि कांग्रेस पार्टी ने आप को दिल्ली चुनाव हराने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने आगे पुष्टि की कि कांग्रेस दिल्ली में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगी और आगामी चुनावों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगी।

गहलोत ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णत: निराधार हैं। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है जहां उनका कोई

आधार ही नहीं था परन्तु केवल कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से आप वहां जाकर चुनाव लड़ी। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी एवं भाजपा की हालत खराब थी वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस के वोटों को बांटा जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इन जगहों पर आप के अधिकतर जीते या हारे उम्मीदवार बाद में भाजपा समेत दूसरी पार्टियों में चले गए। यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। भाजपा ने दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया और आप को सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में वापसी की। इसने 70 में से 48 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि आप की पिछली सीटों की संख्या 62 से भारी गिरावट के साथ 22 रह गई।

मुफ्त की योजनाओं के एलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि उन्हें राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से, मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बेघर लोगों की चिंता किए जाने की हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं

होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की तारीख तय

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि वे इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को यह जानकारी दी। वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका एनजीओ एडीआर ने लगाई है।

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार

■ राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
सजा पर बहस 18 को

नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दो लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी।

यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। यहां दो सिखों, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा।

आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप-बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने

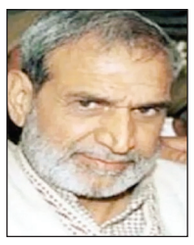

घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया।

अभी सज्जन कुमार दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया।

हमें 40 साल बाद न्याय मिला : आत्मा सिंह लुबाना

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराया है, इसी को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष आत्मा सिंह लुबाना ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस केस को रोक दिया लेकिन मोदी सरकार आने के बाद पीएम मोदी ने एसआईटी का गठन किया और इस केस की समीक्षा की गई।

आत्मा सिंह लुबाना ने कहा कि बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। गवाहों को धमकी दी गई लेकिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने उनका समर्थन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आज इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। हम इस मामले को दोबारा खोलने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि मामला सरस्वती विहार का है, यहां एक पिता और उसके बेटे को जला दिया गया।

भाजपा नेता ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें अपने नेताओं से निर्देश मिले थे। हम पीएम मोदी, एचएम शाह के आभारी हैं, एसआईटी बनी, मामला फिर खुला। कोर्ट ने उसे दोषी पाया, फांसी की सजा होनी चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां लोगों की बेरहमी से हत्याएं की गईं और महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया, हमें न्याय के लिए 40 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सरकार उन्हें आश्रय दे रही थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दोबारा जांच की गई और एक एसआईटी का गठन किया गया। हमने सभी गवाहों का पीछा किया। हम न्यायाधीश को उनके निडर फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं।

राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा : फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि भले ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए, फिर भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा और इसे लोगों के समर्थन की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य का मुद्दा कई वर्षों से है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य का दर्जा बहाल हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन क्या लोग सोचते हैं कि इससे यहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि यहां आतंकवाद खत्म हो गया है, उनसे पूछें कि क्या यह अभी भी है या नहीं।

अब्दुल्ला ने कहा कि कल ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट में दो जवान शहीद हो गये। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि वह कहां से आया? जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हमें लोगों की मदद की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हमें शांति स्थापित करनी चाहिए। यहां शांति ही कुछ कर सकती है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। जब शांति नहीं है तो इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग परिणाम आ सकते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की भावना अभी भी वही है। लेकिन दिल्ली में कुछ गलतियां हुई हैं। अगर आप और कांग्रेस के बीच सही तालमेल होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे. हमें मिलना होगा और इन मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है।

खेल
प्रमुख समाचार

बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी से क्यों किया बाहर?

नईदिल्ली। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की, जिससे टूर्नामेंट में उनके भाग लेने की अटकलों पर विराम लग गया।

19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा।

बुमराह को ट्रेनर रजनीकांत और फिजियो तुलसी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैब से पहले पांच सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई थी। एनसीए प्रमुख नितिन पटेल ने बताया कि हालांकि बुमराह ने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और स्कैन संतोषजनक थे, लेकिन यह अनिश्चित है कि वह टूर्नामेंट की शुरुआत तक गेंदबाजी करने के लिए फिट होंगे या नहीं। बीसीसीआई के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि चयनकर्ताओं ने एक अनफिट खिलाड़ी को शामिल करने का जोखिम नहीं उठाया।

अहमदाबाद में मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ चर्चा के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को यह निर्णय लेने का काम सौंपा गया। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि अनफिट बुमराह को शामिल किया जाए या राणा को चुना जाए, जिनके पास अनुभव की कमी है। मैच के दौरान बुमराह के चोटिल होने का जोखिम बहुत अधिक माना गया। एनसीए को पहले भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के लिए बुमराह को आगे बढ़ाया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक साल के लिए बाहर होना पड़ा था। इस घटना ने अगरकर को इस बार जोखिम न लेने के फैसले को प्रभावित किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 123 अंक टूटा निफ्टी 23,045 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार (12 फरवरी) को लगातार 6ठें ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी50 शुरुआती कारोबार में 1 फीसदी से ज्यादा फिसलने के बाद अंत में हल्की गिरावट लेकर बंद हुए। पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाज़ार में निराशा का माहौल छाया हुआ है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 100 से ज्यादा अंक गिरकर खुला। कुछ ही देर में इसमें गिरावट बढ़ गई। कारोबार के दौरान यह 75,388 अंक तक गिर गया था। कारोबार के दूसरे भाग में इंडेक्स में रिकवरी आई। अंत में यह 122.52 अंक या 0.16% गिरकर 76,171 पर बंद हुआ। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी आज 26.55 अंक या 0.12% की गिरावट लेकर 23,045.25 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 22,798.35 अंक के नीचले स्तर तक चला गया था।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने बटोरे रु.39,687 करोड़

नईदिल्ली। जनवरी 2025 के म्यूचुअल फंड डेटा जारी हो गए हैं। इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुल 39,687 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया, जो दिसंबर 2024 में आए 41,155 करोड़ रुपये से 3.6% कम है। हालांकि, यह 2024 के औसत मासिक इनफ्लो से 21% ज्यादा रहा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 67.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सभी तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कुल 1.88 लाख करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो आया। इक्विटी फंड्स की 11 सब-कैटेगरी में सबसे ज्यादा निवेश थीमैटिक फंड्स में हुआ, जिसमें 9,017 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया। इसके बाद, स्मॉलकैप फंड्स में 5,721 करोड़ रुपये और फ्लेक्सीकैप फंड्स में 5,698 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। गौर करने वाली बात यह रही कि स्मॉलकैप फंड्स में निवेश 22% बढ़ा।

गोल्ड ईटीएफ में निवेश करीब 6 गुना बढ़ा

नईदिल्ली। इक्विटी में लगातार गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत में नए साल की शुरुआत यानी जनवरी के दौरान गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ। यह लगातार 9वां महीना है जब घरेलू स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में नेट इनफ्लो दर्ज किया गया है। इससे पहले बीते साल अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में नेट आउटफ्लो देखा गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 18 गोल्ड ईटीएफ में जनवरी 2025 के दौरान रिकॉर्ड 3,751.42 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इससे पहले सबसे ज्यादा मंथली नेट इनफ्लो (+1,961.57 करोड़ रुपये) बीते साल अक्टूबर में आया था। पिछले साल की समान अवधि यानी जनवरी 2024 के मुकाबले यह 471 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान देश के कुल 16 गोल्ड ईटीएफ में 657.46 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था।

टीवीएस मोटर कर्नाटक में 2,000 करोड़ का निवेश करेगी

नईदिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने बुधवार को कहा कि वह अगले पांच साल में कर्नाटक में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी की योजना क्षमता केंद्र स्थापित करने और उत्पादन बढ़ाने की है। कंपनी ने कहा कि कर्नाटक सरकार के साथ किए गए समझौते के तहत वह एक वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगी, मैसूर में अपनी उत्पादन और इंजीनियरिंग क्षमताओं का विस्तार करेगी, एक परीक्षण ट्रैक का निर्माण करेगी और राज्य में एक नया कंपनी कार्यालय बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कर्नाटक निवेश शिखर सम्मेलन 2025 में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' (जीआईएम) में कंपनी की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहां महान विचार पनपते हैं और कंपनी राज्य में अपना विस्तार करने को उत्साहित है।

अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती के बीच विकसित भारत की उड़ान पर नजर

जीएन बाजपेयी

आखिरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती ने नीति निर्माताओं को परेशान किया और लोगों के बीच बहस भी हुई। अनेक आलोचकों ने मांग में आयी कमी को सुस्ती का मुख्य कारण बताया। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बजट तैयार करते समय नीति निर्माताओं के सामने मुख्य प्रश्न यह था = धुंधले आर्थिक भविष्य के बीच, जिसे बदलते वैश्विक परिदृश्य ने और भी बदतर बना दिया है, सरकार विकसित भारत का उद्देश्य कैसे सुनिश्चित कर सकती थी? घरेलू मोर्चे पर सुस्ती की स्थिति कमोबेश बदलती दिख रही है। लेकिन वैश्विक मोर्चे पर अर्थव्यवस्था कठोर अमेरिकी व्यापार नीतियों, मजबूत होते डॉलर और भू-राजनीतिक दोहरेपन से जूझ रही है। यह स्वीकार करना चाहिए कि इस बार के बजट को डिजाइन करना बहुत कठिन था। ऐसे में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यापक आर्थिक स्थिरता कायम करने, निवेश के पक्ष में माहौल बनाने और उपभोग बढ़ाने जैसे असंभव समझने वाले तीन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुईं, तो यह कम बड़ी बात नहीं है।

इस साल के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.8 प्रतिशत रखा गया है, जो विगत जुलाई के बजट में तय किये गये लक्ष्य से कम है। हालांकि 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और भी कम 4.5 फीसदी रखा गया है। मौद्रिक साख का पता इससे भी चलता है कि जीडीपी में कर्ज की जो हिस्सेदारी 2024-25 में 57.1 प्रतिशत है, उसमें अगले वित्त वर्ष में एक फीसदी की कमी की जानी है, और 2030 तक इसे घटाकर 50 फीसदी किया जाना है। बजट में कुल उधारी 14.83 ट्रिलियन है, पिछले बजट

की तुलना में इसमें मात्र 5.6 फीसदी की वृद्धि है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.1 फीसदी आंकी गयी है, जिससे राजस्व और खर्च के आकलन को स्वाभाविक ही प्रेरणा मिलती है, और यह रिजर्व बैंक को भी संतुलनकारी भूमिका निभाने की दिशा में यह संदेश है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का सिलसिला इस बजट में भी जारी रहा। वित्त वर्ष 2019 में यह जीडीपी का 1.5 प्रतिशत था, जो इस बजट में जीडीपी का 3.2 फीसदी है। पिछले चार साल में इसमें दोगुनी वृद्धि हुई है। अगले साल के बजट में इसका आवंटन 11.2 ट्रिलियन किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित आकलन से 10.9 प्रतिशत ज्यादा है। ढांचागत निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में पूंजीगत निवेश बढ़ेगा।

बजट में टैक्स कटौती बढ़ाकर बजट का 0.3 फीसदी किया गया है, जिससे निश्चित रूप से उपभोग को गति मिलेगी। आयकर के मद में एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की कटौती ने मध्यवर्ग के दो करोड़ से भी अधिक आयकरदाताओं के, जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा, चेहरे पर चमक ला दी है। अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि टैक्स में 80 प्रतिशत की कटौती मांग बढ़ाने और 20 फीसदी की कटौती बचत के लिए की गयी है। बजट में उपभोग को गति देने की दिशा में उठाया गया यह कदम वस्तुत: उन आलोचकों को जवाब है, जिनका कहना था कि पिछले साल उपभोग की मांग हतोत्साहित हुई है। इस बजट के प्रस्तावों को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है = अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घावधि। अल्प अवधि में बजट जीडीपी ग्रोथ की भरपाई करता है, मध्य अवधि में यह उच्च जीडीपी वृद्धि दर के टिकाउपन की बात करता है और दीर्घावधि में यह समृद्धि के अवसर तैयार करता है। यह बजट कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र समेत अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को कवर करता है। यह ग्रामीण भारत के साथ-साथ शहरी भारत के कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है, और इस अर्थ में समावेशी है। जबकि अर्थव्यवस्था के छह क्षेत्रों में रूपांतरकारी सुधार प्रस्तावित किये गये हैं। ये क्षेत्र हैं-ऊर्जा, खनन, पेयजल समेत शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, इज ऑफ डुइंग बिजनेस व लिविंग तथा टैक्स। मेडिकल टूरिज्म समेत पर्यटन, जिसमें कुल 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की गयी है, चमड़ा तथा वस्त्र उद्योग और समुद्री उत्पादों पर विशेष फोकस किया गया है।

भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मलेन में उमड़ी भीड़ व्यापारी,सीए,डॉक्टर ,वकील ,युवा बड़ी संख्या में हुए शामिल

बजट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा फायदा: जोशी

यूपीए सरकार में योजनाओं को शुरू होने में कई साल लग जाते थे, लेकिन आज

रायपुर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केन्द्रीय बजट पर आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को सम्बोधित करते कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की पथ पर तेजी से अग्रसर है।

श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यूपीए की सरकार में देश के उद्योग-धंधों को लगाने के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों और उद्योपतियों को राजनीतिक भ्रष्टचार का शिकार होना पड़ता था, साथ ही उस वक्त की उद्योग नीति का दंश व्यापारियों को झेलना पड़ता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब उद्योगों और व्यापार को बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। इसके पीछे कारण है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक करप्शन खत्म होना। साथ ही छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उद्योग धंधों के विस्तार करने के साथ ही विकास के कार्य को धरातल स्थल पर उतारने के लिए तुरंत क्रियान्वयन किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस सहित पूर्ववर्ती अन्य सरकारों में किसी भी योजना को लागू होने पर 20 साल तक का समय लग जाता था। आज पीएम मोदी की सरकार ने 11 सालों में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कई गुना अधिका काम किया है। यही कारण है भारत आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी जी का संकल्प है कि 2029 तक विश्व की तीसरी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस अवधारणा को समाहित करते हुए ही इसमें जनकल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं।

श्री जोशी ने कहा इंफ्राट्रक्चर के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। इसमें सड़क, रेल से लेकर एयरपोर्ट,पोर्ट सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। पीएम मोदी की सरकार ने केंद्रीय बजट में गरीब-मध्यम वर्ग के लिए बड़ी योजनाओं को प्रावधान है। इसमें मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए सालाना आय को टैक्स मुक्त कर, ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज हम केंद्रीय बजट को लेकर विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, जहां उद्योगपतियों और व्यापारियों के अलावा बुद्धिजीवियों से विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव ले रहे हैं। ताकि सबके सुझाव के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी के साथ प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में तीन-चार प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रख कर काम हुआ है। विकसित भारत के लक्ष्य पर बढने के लिए मोदी जी की सोच है कि मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना है। साथ देश में अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क-रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टविटी को बढ़ाकर देश के छोटे शहरों और महानगरों की दूरियों को खत्म करना। ताकि व्यापार को एक नया स्वरूप दिया जा सके और लोगों के बनाए हुए उत्पाद देश के हर राज्यों में आसानी से पहुंच सके।

श्री जोशी ने कहा कि इंफ्राट्रक्चर के क्षेत्र में 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम 60 सालों में काम नहीं हुए। पहले 9 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़के बनती थी अब 42 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रही हैं।

श्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। चीन और अमेरिका के साथ मिलकर चलना है हमारे लोगों की स्किल भी बढ़नी चाहिए और हमारी स्पीड भी बढना चाहिए और इसलिए हमने कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। उनहोंने कहा कि आज भारत युवा शक्ति के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऐसे में हमने युवाओं के कौशल विकास के साथ ही शोध और अनुसंधान पर जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि आज यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे। जिसमें हजारों उत्पादकों में पेटेंट हासिल हुए हैं, जो एक विश्व रिकार्ड ही है।

श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा रेलवे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में रिकार्ड काम हुए हैं। मोदी सरकार में रेलवे का बजट 300 करोड़ से लगभग 7 हजार करोड़ पहुंच गया है।अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नंदन जैन ने किया ,स्वागत भाषण सीए अमित चिमनानी ने दिया तथा आभार प्रदर्शन नरेश चंद गुप्ता ने किया।इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, सुरेंद्र पाटनी,विजय शंकर मिश्रा, राजेश अग्रवाल प्रीतेश गांधी, आकाश विग मैजूद रहे।

हर वर्ग और प्रत्येक सेक्टर के विकास को ध्यान में रखने वाला कल्याणकारी बजट है: साव

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री अलग-अलग स्थान में सरकार बजट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। अब तक पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बजट के बारे में हमारी धारणा थी कि कुछ और हुआ करती थी कि यह लगता था यह सरकार का लेखा-जोखा है। लेकिन केंद्र सरकार के बजट से अलग-अलग वर्गों के लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पडने वाला है। यह सारी बातें की चर्चा आम व्यक्ति तक जानी चाहिए। इस उद्देश्य से हमारे केंद्रीय मंत्रियों का अलग-अलग राज्यों में प्रवास हो रहा है। पहली बार कोई सरकार बजट को लेकर लोगों के बीच जा रही है और विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव ले रही है

अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में हमारे देश को क्या मूलभूत जरूरतें होगी, क्या होने वाली है। उन सब को ध्यान में रखकर हमारे देश का बजट बन रहा है। आज हम विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि 2047 में भारत की स्वरूप में है। इस कल्पना को लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। पेश हुआ बजट 2025-26 में विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना है। कहा कि मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए युवाओं पर केंद्रित किया है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा को पूरा फोकस किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में को भी प्रमुखता दी गई है। अरुण साव ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

बाबू भैया की कलम से ✍

केंद्र सरकार का संकल्प बनाम नक्सलवाद

बस्तर के नक्सल क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने में आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की लगातार सफलता ने नक्सल हौसले को काफी हद तक तोड़ने का काम किया है। यह साफ दिखाई भी पड़ रहा है। सुरक्षा बलों की आक्रमकता व सूचनाओं से लेस हो जाने का भय नक्सलियों को हताश व निराश करता प्रतीत होने लगा है। कहीं ना कहीं ऐसे निर्देश सुरक्षा बलों को हैं ,जिससे सुरक्षा बल को फ्री हैंड दिया गया प्रतीत होता है। प्रदेश सरकार द्वारा भी सुरक्षा बलों का लगातार उत्साह वर्धन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर में ग्रामीण ओलम्पिक के आयोजन में शिरकत करना तथा खुले आम चुनौती भरे शब्दों में यह घोषणा करना कि 31 मार्च 2026 तक हम बस्तर सहित देश के सभी प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगें। इस घोषणा व उनके कहे शब्दों की कड़ाई में संभवत: सुरक्षा बलों के लिए बड़े संकेत छुपे थे। इससे सुरक्षा बलों को गहन बीहड़ में नक्सलियों के कोर इलाके में घुसने व ऑपरेशन करने का हौसला व साहस में अपार वृद्धि देखी जा रही है। आये दिन उन्हें नक्सल गतिविधियों की जानकारियां मिलने में स्थानीय लोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग भी मिलने लगा है। खबर मिलते ही जिस तरह की सभी बलों व राज्यों की सामूहिक रणनीति से व्यूह रचना कर निरंतर सफलता हासिल की जा रही है,वह ग्रामीणों के लिए उत्साह जनक है। अब तक लगभग 414 नक्सलियों के मारे जाने की खबर से प्रदेश में भी यह बात चल पड़ी है कि अमित शाह की घोषणा की तरफ सुरक्षा बलों के कदम बढ़ रहे हैं। कुछ गंभीरता से रणनीति बनी है ,यह आभास होने लगा है। इस बीच कुछ निरपराध लोगों के मारे जाने की संभावना विपक्ष द्वारा जताई जा रही है। यह संभावना यूँ ही नहीं है,जब भी कोई बडा ऑपरेशन होता है तो वहां मौजूद ग्रामीण भी हताहत होते ही होंगे। पंजाब से आतंकवाद तब खत्म हो पाया जब बड़े ऑपरेशन में कुछ स्थानीय लोगों को भी अपनी शहादत देनी पड़ी। हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीणों की हत्या की जाए। सुरक्षा बलों को निर्देश होते हैं कि निर्दोष लोग हताहत ना हों ,इस बात का ध्यान रखा जाए। नक्सल क्षेत्र में कौन नक्सली है ,कौन ग्रामीण अनेक मौकों पर यह फर्क करना कठिन हो जाता है। इसलिए भी चूक होने की संभावना होती है। अब जब नक्सलवादी हताश व निराश दिखाई देने लगे हैं ,तो सभी दलगत राजनीति से उठकर नक्सल ऑपरेशन को जायज ठहराएं यह उम्मीद की जाती है। सुरक्षाबलों की आक्रमकता व सुनियिजित रणनीति के कारण मुठभेडों में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं। नक्सलियों के अग्रणी नेताओं को लक्ष्य किया गया है। अनेक इनामी नक्सली लीडर मौत के घाट उतारे गए हैं। रणनीति यह दिखाई देती है कि शीर्ष लीडरशिप समाप्त कर दी जाए। लीडरशिप के अभाव में बाकी नक्सलियों की कमर टूटेगी,और वे बगैर नेतृत्व , हताश होकर प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने बाध्य होंगें। लगातार कुछ नक्सलियों का सरेंडर किया जाना भी इस बात की पुष्टि करता प्रतीत होता है। प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी की माने तो प्रदेश में लगभग 4000 हजार नक्सलियों की उपस्थिथि थी। उन्हें सहयोग करने वाले भी 40000 के करीब हैं। अगर यह आंकड़ा सही माने तो नक्सलियों के इस चक्रव्यूह को तोड़ना आसान काम नहीं है। इस दिशा में नक्सल शीर्ष लीडर जिस तरह से लगातार मारे जा रहे हैं,उससे यह उम्मीद तो जाग रही है कि इसी तरह की रफ्तार बनी रही तो 2026 की गारंटी तो नहीं लेकिन एक न एक दिन नक्सलवाद समाप्त होने की संभावना बन जाएगी। 9 फरवरी को नक्सलियों के सुरक्षित कोर क्षेत्र इंद्रावती नेशनल पार्क के गहन जंगल में पुख्ता जानकारी के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। शेष नक्सली अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग खड़े हुए। उनको भी सुरक्षा बल वहीं डटकर खोजने में जुटे है। यह बात ही नक्सलियों के उखड़ते पैरो का व सुरक्षाबलों के हौसले का सबूत दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियार भी बरामद करने में बल को सफलता मिलती जा रही है। यह भी नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। हथियार की कमी भी नक्सलियों के हौसले को कमजोर करने का काम करेगी। लंबा अरसा गुजरा नक्सल ,सुरक्षा बलों या थानों पर हमला करके हथियार लूटने की घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं। बाहरी सहयोगियों पर भी सरकार व सुरक्षा बलों की नजर है,ताकि हथियारों की आमद नक्सलियों को ना हो पाए। पहली बार केंद्र सरकार व राज्य सरकारें साथ मिलकर वाकई सही व सटीक रणनीति से मिलकर काम करती दिखाई दे रहीं है। अब वे खबरें नहीं दिखाई देती कि नक्सली अंधेरे व जंगल की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए। यह भी नहीं कि नक्सलियों ने जवानों को अपने एम्बुश में फंसा कर जवानों को शहीद होने मजबूर कर दिया हो। अब आये दिन बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने व हथियार बरामद होने की खबर यह उम्मीद तो जगा ही देती है कि सम्भवत: वाकई एक साल में नक्सल समस्या से निजात मिल जाएगी और हमारा बस्तर भी विश्व पर्यटन के नक्शे में बड़ा स्थान बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर लेगा। अंत में नक्सल आतंक समाप्त होने की मंगल कामना करते हुए,बस्तर के इस उद्धार के लिए अपनी शहीदी देने वाले समस्त सुरक्षा बलों व अन्य शहीदों को नमन है। यह कामना भी करते हैं कि 2026 मार्च के बाद हमारा बस्तर क्षेत्र का पर्यटन देश विदेश के लिए और भी आकर्षण का केंद्र बने।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रायपुर सहित सभी निगमों में कांग्रेस जीतेगी: दीपक बैज

रायपुर। रायपुर सहित सभी निगमों में कांग्रेस जीतेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निकाय चुनाव में मतदान के बाद जो तस्वीर साफ हुई उससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अधिकांश निकायों में चुनाव जीतेगी। प्रदेश में

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातारण है। लोग प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण सरकार से निराश है, भाजपा की साय सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराश किया है। इसीलिये जनता ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा सरकार की नाकमी और वादाखिलाफी पर लड़ा गया। पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश है। सब सरकार के अपने आपको ठगा महसूस कर रहे है। भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही।

केंद्र की नाकामी ढकने जोशी झूठ बोलने छत्तीसगढ़ आए: शुक्ला

रायपुर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बजट की तारीफ करने छत्तीसगढ़ आये थे लेकिन बजट मे छत्तीसगढ़ के

लिए क्या है यह छ्ग की जनता को नहीं बता पाए। केंद्रीय बजट मे छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा देश की जनता के सामने जो बजट रखा गया है उसमें जनता की भलाई कहीं नजर नहीं आ रही है इस बजट से ना तो बेरोजगारी दूर होगा ना महंगाई कम होगी ना किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। अमृत काल में देश की जनता मोदी की महंगाई काल की मार को झेल रही है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने जो एक मजबूत भारत का निर्माण किया था उस भारत को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम मोदी सरकार ने 11 साल में किया है। मोदी सरकार का 2025 का जो बजट है उस में मनरेगा के फंड में कटौती कर दिया गया शिक्षा फंड में कटौती किया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्कीम में कटौती किया गया है किसानों को राहत देने कोई प्रोग्राम नहीं है इससे समझ में आता है कि बजट गरीब विरोधी है। गरीब के आटा दूध और रसोई गैस के दाम कैसे कम हो इस पर चर्चा करने से मोदी सरकार सदन से भागती है।

कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा परेशान: बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले को लेकर ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनके करीबियों से बुधवार को

पूछताछ की। इसके लिए एजाज ढेबर अपने वकील के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। इस बीच ईओडब्ल्यू की पूछताछ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सरकार के पास कोई और काम नहीं है। ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू सभी एजेंसियां सिर्फ यही काम कर रही हैं। एक एजेंसी की जांच खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। बस बुला-बुलाकर परेशान किया जा रहा है।पूर्व महापौर एजाज ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा कि उनके मुवक्किल पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। चुनाव के दौरान व्यस्तता के कारण वह पहले नोटिस का जवाब नहीं दे सके थे, लेकिन अब वे अधिकारियों द्वारा मांगे गए हर सहयोग को देने के लिए तैयार हैं। अमीन खान ने कहा, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और जो भी आवश्यक होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में ईडी ने राज्य की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू-एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी।

सीएम साय ने दाऊ कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी दानशीलता के लिए विख्यात समाजसेवी दाऊ कल्याण सिंह की 13 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दाऊ

कल्याण सिंह जी समाज के उत्थान के लिए समर्पित ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिनकी दानशीलता और उदारता सदैव प्रेरणा देती रहेगी। दाऊ कल्याण सिंह एक युगदृष्टा थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा के लिए अद्वितीय योगदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दाऊ कल्याण सिंह ने अस्पताल, पुस्तकालय, कॉलेज, जलाशय जैसी जनहितकारी संस्थाओं के लिए कई एकड़ भूमि दान में दी। उनके इस योगदान के कारण प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज उनके द्वारा दान में दी गई भूमि पर अनेक शिक्षण संस्थान और चिकित्सालय संचालित हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले दाऊ कल्याण सिंह जी का नाम सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका जीवन हम सभी को सार्वजनिक हितों के लिए निस्वार्थ कार्य करने की प्रेरणा देता है।

निकाय चुनाव मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 अप्रैल को मतदान हो गया है. 15 अप्रैल को चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन इस बीच मतदान और उसकी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं.ईवीएम को लेकर मचा घमासान - कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराबी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, परिसीमन में खामी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस को खुली चुनौती दी है कि यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो किसी आईटी एक्सपर्ट से इसे साबित करें. भाजपा ने तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस को न्यायालय जाने की भी सलाह दी है.कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही डरी हुई थी. भाजपा को हार का डर सता रहा था, इसलिए नगरी निकाय चुनाव को पहले टालने की कोशिश की गई. इसके बाद परिसीमन में गड़बड़ी की, त्रुटि पूर्ण मतदाता सूची को प्रकाशित करवाया और जो कांग्रेस से कोर वोटर थे, वहां पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उस बूथ को कई भागों में बांटा गया.मतदाता सूची में इतनी गलतियां थी, कि जीवित लोगों का नाम काट दिया गया. मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल थे. एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में शामिल था. जिस कारण पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है।

राजिम कुंभ कल्प 2025 का होगा आगाज

माघ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई डुबकी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम में आज राजिम कुंभ कल्प 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है. वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर सुबह त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. महानदी में स्नान कर श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और कुलेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की.

आज शाम राज्यपाल रमेन डेका कुंभ का शुभारंभ करेंगे, जो 26 फवरी तक चलेगा. उद्घाटन कार्यक्रम में बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी. बता दें कि 20 साल बाद मेला स्थल को बदला गया है. मेला अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लग रहा, जहां 54 एकड़ भूमि पर भव्य मंच तैयार किया गया है. इस बार देशभर से प्रख्यात संत-महापुरुषों की उपस्थिति इस महाकुंभ को दिव्यता प्रदान करेगी.

पंचकोशी धाम थीम पर विशेष आयोजन

इस वर्ष मेले की थीम पंचकोशी धाम पर आधारित होगी, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और संस्कृति का भव्य अनुभव प्रदान करेगी। इस आयोजन के तहत धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, संत समागम और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा. इसके साथ ही 21 फरवरी से 26 फरवरी तक विराट संत समागम होगा. इस दौरान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 21 फरवरी जानकी जयंती और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को पर्व स्नान भी होंगे, जिसमें शाही जुलूस भी निकाली जाएगी. 12 फरवरी सुबह माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पुण्य स्नान करेंगे. पुण्य स्नान पश्चात भगवान श्री राजीव लोचन एवं श्री कुलेश्वर महादेव, दानदानेश्वर, बाबा गरीबनाथ, लोमष ऋषि आश्रम दर्शन कर पुण्य लाभ लेंगे.

भक्तों और संतों का महासंगम

राजिम कुंभ कल्प मेले में देशभर से साधु-संतों, कथा वाचकों और श्रद्धालुओं का आगमन होगा। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, लोककला और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन इस बार के कुंभ कल्प मेले को विशेष बनाएगा। मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, रुकने और खाने-पीने की विशेष व्यवस्था की गई है।

पंडोखर सरकार का लगेगा दरबार

नदी क्षेत्र में बनाए गए संत समागम स्थल पर 21 फरवरी से 25 फरवरी तक दतिया म.प्र. से पहुंचे गुरुशरण महाराज (पंडोखर सरकार) का सत्संग दरबार लगाया जाएगा। महाराज शाम 4 बजे से 7 बजे सत्संग करेंगे। इसी प्रकार 13 फरवरी से 19 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जहां उदयपुर राजस्थान से पधारे डॉ. संजय कृष्ण सलिल जी महाराज प्रवचन देंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जाताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय अनुसूची कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन 2025 निर्धारित तिथि 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सम्पन्न हुआ। प्रदेश के 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद् एवं 114 नगरपंचायतों सहित 173 नगरीय निकायों के लिए एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ. नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु मतदाताओं की कुल संख्या 44 लाख 75 हज़ार 703 है. जिसमें से सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसत मतदान कुल 72.48

फीसदी रहा. मतगणना 15 फरवरी 2025 को संपन्न कराया जाना है

नगरपालिका आम निर्वाचन मतदान मशीन ईवीएम से कराया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मतदान के दौरान 12 हज़ार 500 कंट्रोल यूनिट तथा 22 हज़ार 650 बैलेट यूनिट उपयोग में लाये गये। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत बसना जिला-महासमुंद में अध्यक्ष पद अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तथा आम निर्वाचन में कुल 31 एवं उप निर्वाचन में 02 पार्षद पद के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

निर्वाचन के दौरान जिला - खैरागढ़- छुईखदान - गण्डई में 01, जिला-गरियाबंद में 01, जिला- जांजगीर चांपा में 03, जिला-दंतेवाड़ा में 05, जिला-महासमुंद में 03, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज में 03, जिला-सूरजपुर में 05 एवं जिला- मुंगेली से 02 में मतदान मशीन खराब होने के कारण बदलने की सूचना प्राप्त हुई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.